सारांश

मानव विकास रिपोर्ट 2013

दक्षिण का उदयः

विविधतापूर्ण विश्व में मानव प्रगति

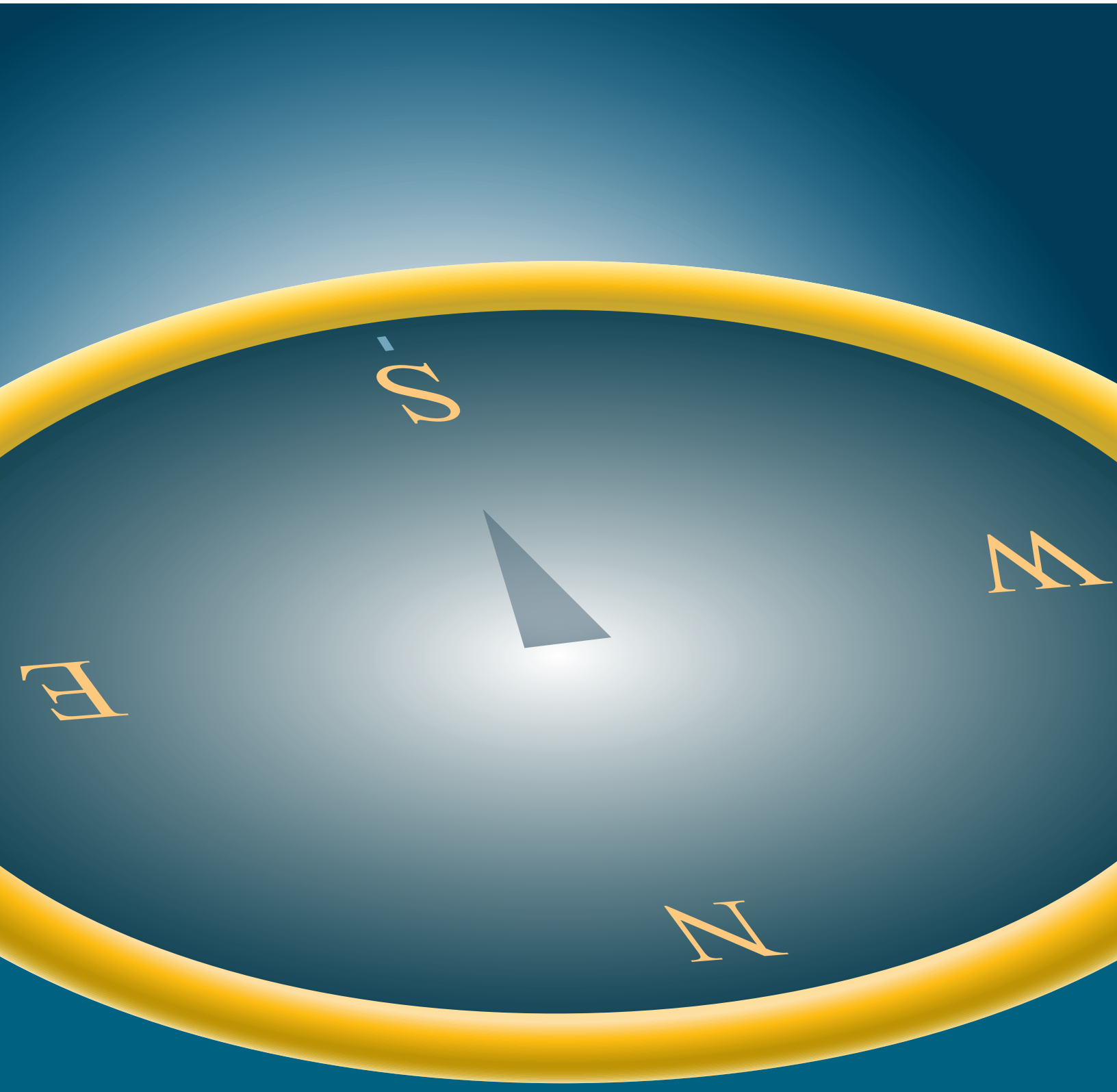

कॉपीराइट © 2013
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा

1 यू.एन. प्लाज़ा, न्यू यॉर्क, एन.वाई. 10017 संयुक्त राज्य अमेरिका

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी अंश पूर्वानुमति के बिना न तो पुनर्प्रकाशित किया जा सकता है, न ही किसी रिट्रीवल सिस्टम में संरक्षित किया जा सकता है अथवा किसी भी रूप में और किसी भी विधि से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फ़ोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग अथवा अन्य किसी तरह से प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

भारत में ब्राइट सर्विसेज़ प्रा. लि. द्वारा मुद्रित

मानव विकास रिपोर्ट के इस सारांश का हिन्दी अनुवाद सम्यक् कम्युनिकेशन्स द्वारा

संपादन एवं प्रोडक्शनः कम्युनिकेशन्स डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेटेड, वाशिंगटन डी.सी.

डिज़ाइनः मेलेनी डोहर्टी डिज़ाइन, सैन फ़्रांसिस्को, सी.ए.

प्रकाशन के बाद भी पाठ में रह गई ग़ल्तियों एवं कमियों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें http://hdr.undp.org

मानव विकास रिपोर्ट 2013 की टीम

निदेशक एवं प्रमुख लेखक
ख़ालिद मलिक

शोध एवं सांख्यिकी
मॉरिस कुगलर (शोध के प्रमुख), मिलोरैड कोवेसेविक (मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी), शुभ्रा भट्टाचार्जी, एस्ट्रा बोनीनी, सिसीलिया कैल्डेरॉन, एलेन फुक्स, एमी गाये, इएना कोनोवा, आर्थर मिन्सेट, शिवानी नय्यर, होज़े पिनेडा एवं स्वर्निम वाघले

संचार एवं प्रकाशन
विलियम ओर्मे (संचार के प्रमुख), बोटागोज़ अब्द्रेयेवा, कार्लोटा आएलो, एलियोनोर फ़ोर्नियर-टूम्बस, ज्याँ-ईव्ज़ हैमेल, स्कॉट लूविस एवं सामन्ता वौचोप

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें
इवा जेस्पर्सन (उप निदेशक), क्रिस्टीना हैकमान, जोनाथन हॉल, मैरी एन मवांगी एवं पाओला पग्लियानी

परिचालन एवं प्रशासन
सरन्तूया मैंड (परिचालन प्रबंधक), इकेटेरीना बर्मन, डाएन बोउपडा, ममाये गेब्रेसादिक एवं फ़े हुएरेज़-शनाहन

सारांश

मानव विकास रिपोर्ट 2013

दक्षिण का उदय :
विविधतापूर्ण विश्व में मानव प्रगति

संयुक्त राष्ट्र
विकास कार्यक्रम
(यू.एन.डी.पी.)
के लिए
प्रकाशित

Empowered lives.
Resilient nations.

आमुख

मानव विकास रिपोर्ट 2013, दक्षिण का उदयः एक विविधतापूर्ण संसार में मानव प्रगति हमारे समय की उभरती भू-राजनीति पर निगाह डालते हुए उभर रहे मुद्दों और प्रवृत्तियों का परीक्षण करती है, और उन नए तत्वों को चिन्हित करती है जो विकास परिदृश्य को गढ़ रहे हैं।

रिपोर्ट दलील देती है कि बड़ी संख्या में विकासशील देशों के गतिमान, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में रूपान्तरित होने का और उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का मानव विकास प्रगति पर उल्लेखनीय असर पड़ रहा है।

रिपोर्ट रेखांकित करती है कि पिछले दशक में सभी देशों ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के आयामों में, जैसे वे मानव विकास सूचकांक में मापे जाते हैं, अपनी उपलब्धियाँ तेज़ की हैं। जिन देशों के आँकड़े उपलब्ध थे, उनमें से 2012 में किसी का भी मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) 2000 के मान से नीचे नहीं था। चूँकि निम्नतर मा.वि.सू. वाले देशों में इस दौरान ज्यादा तेज़ प्रगति दर्ज की गई, इसलिए मानव विकास सूचकांक मूल्यों में विश्व भर में उल्लेखनीय समायोजन (convergence) था, हालाँकि प्रगति, क्षेत्रों के बीच और भीतर भी, असमान थी।

खास तौर पर उन देशों को देखते हुए जिन्होंने 1990 और 2012 के बीच मानव विकास के आय और ग़ैर-आय आयामों में अपने मा.वि.सू. मान में बड़ी प्रगति प्राप्त की, यह रिपोर्ट उन रणनीतियों की पड़ताल करती है, जिन्होंने इन देशों के अच्छे प्रदर्शन को सम्भव बनाया। इस अर्थ में यह 2013 की रिपोर्ट विकास रूपान्तरण के विशिष्ट चालकों-तत्वों के वर्णन और इस प्रगति को बनाए रखने वाली मददगार भावी नीति-वरीयताओं को रेखांकित करके विकास से जुड़े विमर्श में अहम योगदान करती है।

इस रिपोर्ट के लिए विकसित अनुमानों के अनुसार, सन् 2020 तक, सिर्फ़ तीन प्रमुख विकासशील देशों– ब्राज़ील, चीन और भारत– का संयुक्त आर्थिक उत्पादन कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल उत्पादन से आगे निकल जाएगा। इस विस्तार का बहुतांश दक्षिण के भीतर ही नए व्यापार और तकनीकी भागीदारियों द्वारा प्रेरित है, जैसा यह रिपोर्ट भी दर्शाती है।

लेकिन इस और इससे पहले की मानव विकास रिपोर्टों का एक केन्द्रीय संदेश यह है कि अकेले आर्थिक वृद्धि से ही अपने आप मानव विकास प्रगति नहीं होती। ग़रीब-समर्थक नीतियाँ और लोगों की क्षमताओं में भरपूर निवेश– शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गारपरक दक्षताओं पर ध्यान दे कर– प्रतिष्ठापूर्ण काम तक पहुँच का विस्तार करती हैं और टिकाऊ प्रगति को संभव बनाती हैं।

विकास का संवेग टिकाऊ बनाए रखने के लिए 2013 की रिपोर्ट चार स्पष्ट क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करती है– समता में वृद्धि, लैंगिकता के आयामों को शामिल करते हुए; युवाओं सहित नागरिकों की मुखरतर आवाज़ और सहभागिता को बढ़ावा; पर्यावरणीय चुनौतियों का मुकाबला; और जनसांख्यिकीय परिवर्तन का प्रबंधन।

रिपोर्ट यह भी सुझाती है कि जैसे-जैसे वैश्विक विकास चुनौतियाँ ज्यादा जटिल और अपनी प्रकृति में ज्यादा अंतरराष्ट्रीय होती जाती हैं, हमारे समय की सबसे ज़रूरी चुनौतियों, चाहे वह ग़रीबी उन्मूलन हो, जलवायु परिवर्तन हो या फिर शांति और सुरक्षा, उन पर समेकित-समन्वित कार्रवाई अनिवार्य है। चूँकि अब देश व्यापार, आप्रवास, और सूचना संचार तकनीकों द्वारा अधिकाधिक अंतरसंबद्ध हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एक जगह के नीतिगत निर्णय दूसरी जगहों पर भी भरपूर असर डालते हैं। पिछले कुछ सालों के संकट– खाद्य, वित्तीय, जलवायु– जिन्होंने इतने लोगों की ज़िन्दगियों को नुकसान पहुँचाया, यही दिखाते हैं। साथ ही दिखाते हैं झटकों और आपदाओं के प्रति लोगों की अरक्षितताओं को कम करने के लिए काम करने की ज़रूरत को भी।

दक्षिण में मौजूद ज्ञान, दक्षताओं और विकास चिंतन का लाभ उठाने के लिए यह रिपोर्ट ऐसी नई संस्थाओं की माँग करती है जो क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सक्षम बना सकें। विकासशील दुनिया की उभरती शक्तियाँ पहले ही दूसरे विकासशील देशों के लिए नवाचारी सामाजिक और आर्थिक नीतियों की स्रोत हैं और उनके व्यापार, निवेश और बढ़ते विकास सहयोग की प्रमुख भागीदार भी हैं।

दक्षिण में बहुत से दूसरे देशों में तेज़ विकास हुआ है और उनके अनुभव तथा उनका दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकास नीति के लिए समान रूप से प्रेरक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ज्ञान-मध्यस्थ की और साझीदारों– सरकारों, नागर समाज और बहुराष्ट्रीय कंपनियों– के संयोजक की उपयोगी भूमिका निभा पाता है ताकि अनुभव बाँटे जा सकें। अधिगम (ज्ञान-प्राप्ति) और क्षमता वृद्धि को संभव बनाने में हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह रिपोर्ट दक्षिण-दक्षिण सहयोग से जुड़े हमारे भावी कार्य के लिए बहुत उपयोगी अंतर्दृष्टियाँ देती है।

अंत में, यह रिपोर्ट एक ज्यादा न्यायसंगत, समतापूर्ण संसार बनाने के लिए वैश्विक अधिशासन संस्थाओं पर एक आलोचनात्मत दृष्टि डालने का आह्वान करती है। यह कालबाह्य ढाँचों को चिन्हित करती है जो नए आर्थिक और भू-राजनीतिक यथार्थ को प्रतिबिंबित नहीं करते, और भागीदारी के एक नए युग के लिए विकल्पों पर विचार करती है। यह बृहत्तर पारदर्शिता और जवाबदेही का आह्वान करती है, और इसके लिए वैश्विक नागर समाज की भूमिका को तो रेखांकित करती ही है, साथ में वैश्विक बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों– जो अक्सर हमारे संसार के सबसे निर्धन और अरक्षित इन्सान होते हैं– के लिए अधिक निर्णयन शक्ति की बात पर भी ज़ोर देती है।

वर्ष 2015 के बाद के वैश्विक विकास एजेंडे पर चर्चा जारी है, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत से लोग इस रिपोर्ट को पढ़ने का और तेज़ी से बदलते हमारे संसार के लिए इसके सबकों पर विचार करने का समय निकालेंगे। वैश्विक विकास की वर्तमान स्थिति की हमारी समझ को यह रिपोर्ट फिर ताज़ा करती है, और दिखाती है कि दक्षिण के इतने सारे देशों की विकास की तेज़ प्रगति के अनुभवों से कितना कुछ सीखा जा सकता है।

हेलेन क्लार्क
प्रशासक
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

मानव विकास रिपोर्ट 2013 का अनुक्रम

आमुख

आभार

विहगावलोकन

प्रस्तावना

अध्याय 1

मानव विकास की स्थिति

देशों की प्रगति

सामाजिक एकीकरण

मानव सुरक्षा

अध्याय 2

अधिक वैश्विक होता दक्षिण

पुनर्संतुलनः अधिक वैश्विक विश्व और अधिक वैश्विक दक्षिण

मानव विकास से प्रोत्साहन

दक्षिण में नवाचार एवं उद्यमिता

सहकारिता के नए रूप

अनिश्चित दौर में प्रगति बरकरार रखने की चुनौती

अध्याय 3

विकासपरक रूपान्तरण के प्रेरक

प्रचालक 1. प्रसक्रिय विकासपरक राज्य

प्रचालक 2. वैश्विक बाज़ारों का दोहन

प्रचालक 3. सामाजिक नीति में संकल्पशील नवाचार

अध्याय 4

गति क़ायम रखने की चुनौती

विकासशील देशों के लिए नीतिगत प्राथमिकताएँ

जनसांख्यिकी और शिक्षा के परिदृश्य

आबादी की आयु वृद्धि का प्रभाव

महत्वाकांक्षी नीतियों की आवश्यकता

सही वक्त पर क़दम उठाना

अध्याय 5

नए दौर के लिए अधिशासन एवं साझेदारियाँ

सार्वजनिक साधनों का एक नया वैश्विक नज़रिया

दक्षिण के लिए बेहतर प्रतिनिधित्व

वैश्विक नागर समाज

संगत बहुलता की ओर

ज़िम्मेदार सम्प्रभुता

नई संस्थाएँ, नई कार्यविधियाँ

निष्कर्षः नए दौर के साझीदार

नोट्स

संदर्भ

सांख्यिकीय सारणियाँ

पाठकों के लिए मार्गदर्शिका

कुंजिकाः मा.वि.सू. देश व उनकी श्रेणी, 2012

सांख्यिकीय सारणियाँ

1 मानव विकास सूचकांक एवं उसके घटक

2 मानव विकास सूचकांक की प्रवृत्तियाँ - 1980 -2012

3 असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक

4 लैंगिक असमानता सूचकांक

5 बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

6 संसाधनों पर नियंत्रण

7 स्वास्थ्य

8 शिक्षा

9 सामाजिक एकीकरण

10 वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय प्रवाह

11 अंतरराष्ट्रीय पूँजी प्रवाह एवं प्रवास

12 नवाचार और प्रौद्योगिकी

13 पर्यावरण

14 जनसंख्या की प्रवृत्तियाँ

क्षेत्र

सांख्यिकीय संदर्भ

तकनीकी परिशिष्टः पूर्वानुमान क्रियाविधि पर व्याख्यात्मक टीप

मानव विकास रिपोर्ट 2013 का सारांश

जब 2008-09 के वित्तीय संकट के दौरान विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने बढ़ना बंद कर दिया लेकिन विकासशील अर्थ व्यवस्थाएँ बढ़ती रहीं, तब दुनिया का ध्यान गया। तब से दक्षिण के उदय पर, जिसे विकासशील दुनिया में एक बहुप्रतीक्षित वैश्विक पुनर्संतुलन के रूप में देखा जाता है, काफी टिप्पणियाँ हुई हैं। लेकिन इन चर्चाओं का केन्द्र, संकीर्ण रूप से, कुछ बड़े देशों में सकल घरेलू उत्पाद और व्यापार वृद्धि तक सीमित रहा है। परन्तु उनसे ज्यादा व्यापक अंतः प्रक्रियाएँ काम कर रही हैं– बहुत से और देशों को समेटते हुए, ज्यादा गहरी प्रवृत्तियाँ, लोगों के जीवन पर दूरगामी प्रभावों, सामाजिक समता और वैश्विक व स्थानीय स्तरों पर लोकतांत्रिक अधिशासन की संभावनाओं से भरी। जैसा कि यह रिपोर्ट दिखाती है, दक्षिण का उदय मानव विकास में निरंतर निवेशों और उपलब्धियों का नतीजा है और पूरी दुनिया के लिए और भी व्यापक मानवीय प्रगति की संभावनाएँ पेश करता है। लेकिन उस प्रगति को एक सच्चाई बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी एक जानकार और प्रबुद्ध वैश्विक व राष्ट्रीय नीति-निर्माण की– इस रिपोर्ट में विश्लेषित नीति विकल्पो-सबकों से सीखते हुए।

दक्षिण का उदय

दक्षिण का उदय अपनी गति और आकार में अभूतपूर्व है। इसे व्यापक मानव विकास के संदर्भों में समझा जाना ज़रूरी है। यह उन देशों की, जहाँ संसार की अधिकतर जनसंख्या रहती है, उनकी निजी क्षमताओं के नाटकीय विस्तार और उनकी स्थायी मानव विकास प्रगति की कहानी है। जब दर्जनों देश और अरबों लोग विकास की सीढ़ी चढ़ते हैं, जैसे वे आज चढ़ रहे हैं, तब विश्व के सारे देशों और भागों में पूँजी निर्माण और वृहत्तर मानव विकास पर सीधा असर पड़ता है। इसमें कम विकसित देशों के लिए बराबरी में आने के, और सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी फ़ायदेमंद, रचनात्मक नीतिगत पहलों के नए अवसर हैं।

हालाँकि ज्यादातर विकासशील देशों ने तरक्की की है, उनमें से कइयों की प्रगति ज्यादा ही अच्छी रही है– इसे कहा जा सकता हैः ''दक्षिण का उदय''। सबसे बड़े देशों में से कुछ ने तेज़ तरक्की की है, विशेषतः ब्राज़ील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। लेकिन कई छोटे देशों में भी ठोस प्रगति हुई है, जैसे बांग्लादेश, चिली, घाना, मॉरिशस, रवाण्डा और ट्यूनीशिया (रेखांकन 1)।

दक्षिण के उदय और उसके मानव विकास के लिए फलितार्थों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ 2013 मानव विकास रिपोर्ट इस बदलती दुनिया के बारे में भी है, जो दक्षिण के उदय द्वारा भी काफी हद तक गढ़ी जा रही है। रिपोर्ट समीक्षा करती है हो रही प्रगति की, उभरती हुई चुनौतियों की (जिनमें कुछ इसी प्रगति से जन्मी हैं) और प्रातिनिधिक वैश्विक और क्षेत्रीय अधिशासन के लिए सामने आते अवसरों की।

150 वर्षों में पहली बार, विकासशील दुनिया की तीन मुख्य अर्थव्यवस्थाओं– चीन, भारत और ब्राज़ील– का संयुक्त उत्पादन वैश्विक उत्तर की पारंपरिक औद्योगिक

रेखांकन 1

40 से भी अधिक दक्षिणी देशों ने 1990 से अबतक अपने मा.वि.सू. में महत्वपूर्ण इजाफ़ा किया है, जो उनके पिछले मा.वि.सू. प्रदर्शन के मुकाबले कहीं अधिक है

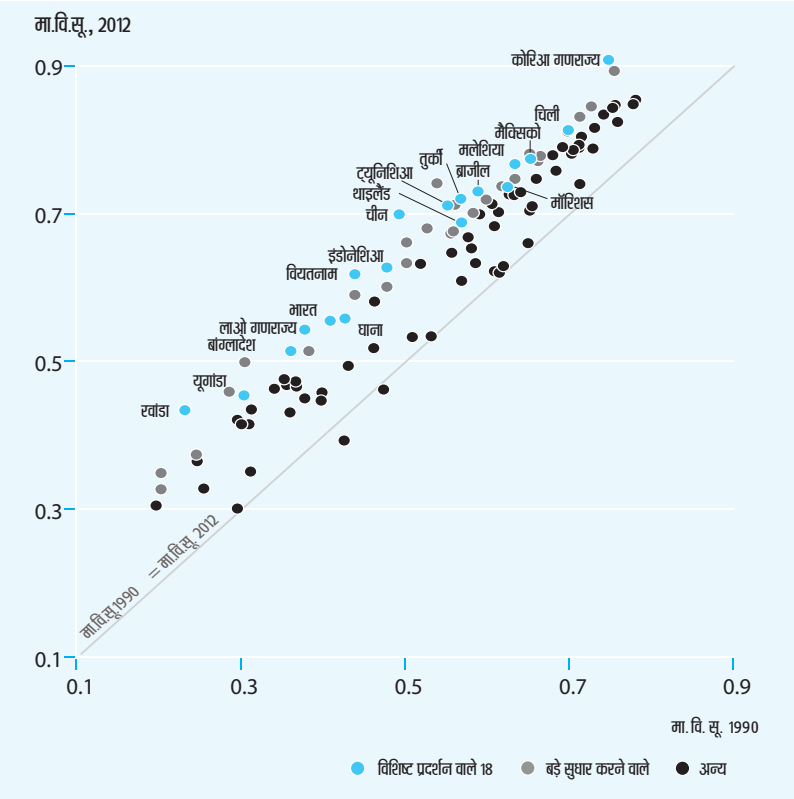

नोटः 45 अंश की पंक्ति के ऊपर वाले देशों का मा.वि.सू. मान 1990 की तुलना में 2012 में अधिक था। सलेटी और नीले बिन्दु उन देशों को दर्शाते हैं जिनके मा.वि.सू. मानों में वृद्धि 1990 और 2012 के बीच पूर्वानमानों से कहीं ज्यादा रही। इन देशों की पहचान 2012 और 1990 के लॉग के मूल्यों के समाश्रयण पर आधारित है। जिन देशों को लेबल किया गया है, वे तेज़ मा.वि.सू. सुधारकों के एक चुने हुए समूह हैं जिनकी विस्तृत चर्चा अध्याय 3 में की गई है।
स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

शक्तियों– कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, युनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका– के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग बराबर है। यह वैश्विक आर्थिक शक्ति का एक नाटकीय पुनर्संतुलन दिखाता है। सन् 1950 में, चीन, भारत और ब्राज़ील मिलकर विश्व अर्थव्यवस्था के 10% हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे, जबकि उत्तर की वे छह पारंपरिक आर्थिक शक्तियाँ आधे से अधिक का। इस रिपोर्ट के पूर्वानुमानों के अनुसार, 2050 तक ब्राज़ील, चीन और भारत मिलकर वैश्विक उत्पादन का 40% पैदा करेंगे, आज के 'सात के समूह' (ग्रुप ऑफ़ सेवेन) के अनुमानित संयुक्त उत्पादन से कहीं ज्यादा।

दक्षिण का मध्यम वर्ग आकार, आय और अपेक्षाओं में तेज़ी से बढ़ रहा है (रेखांकन 3)। दक्षिण में लोगों की विराट संख्या– अरबों उपभोक्ता और नागरिक– सरकारों, कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के दक्षिण में क्रियाकलापों के वैश्विक मानव विकास परिणामों को कई गुना बढ़ा देती है। उत्तर के साथ साथ अब दक्षिण भी तकनीकी नवाचार और रचनात्मक उद्यमिता की उर्वर भूमि के रूप में उभर रहा है। उत्तर-दक्षिण व्यापार में इन नई औद्योगीकृत होती अर्थव्यवस्थाओं ने विकसित देशों के बाज़ारों के लिए निपुणता से जटिल उत्पाद बनाने की क्षमताएँ बना ली हैं। लेकिन दक्षिण-दक्षिण अंतर्क्रियाओं ने दक्षिण की कंपनियों को स्थानीय ज़रूरतों के लिए ज्यादा मुफ़ीद उत्पाद और प्रक्रियाओं के नवाचार में सक्षम बनाया है।

उत्तर के साथ साथ अब दक्षिण भी तकनीकी नवाचार और रचनात्मक उद्यमिता की उर्वर भूमि के रूप में उभर रहा है।

मानव विकास की स्थिति

2012 में मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) काफ़ी तरक्की दिखाता है। पिछले दशक के दौरान संसार भर के देश मानव विकास के उच्चतर स्तरों पर समायोजित हो रहे हैं। मा.वि.सू. प्रगति की रफ्तार निम्न और मध्यम विकास श्रेणी के देशों में सबसे तेज़ रही है। यह अच्छी खबर है। लेकिन प्रगति को मा.वि.सू. में औसत से ज्यादा सुधारों की ज़रूरत है। यह न तो वांछनीय होगा, न ही टिकाऊ अगर मा.वि.सू.में वृद्धि बढ़ती आय असमानताओं, उपभोग के असंवहनीय तरीकों, ऊँचे सैनिक व्यय और नीची सामाजिक समरसता के साथ आती है। (बॉक्स 1 देखें)

मानव विकास का एक ज़रूरी हिस्सा है समता। हर व्यक्ति को अधिकार है अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप एक सार्थक जीवन जीने का। कोई भी व्यक्ति एक छोटा या एक कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए इसलिए अभिशप्त नहीं हो सकता कि वह संयोग से एक 'ग़लत' वर्ग या देश में, 'ग़लत' जाति या नस्ल में या 'ग़लत' लिंग में पैदा हुआ है। असमानता मानव विकास की गति धीमी करती है और कुछ मामलों में इसे पूरी तरह रोक भी सकती

रेखांकन 2

ब्राज़ील, चीन और भारत का संयुक्त निर्गत 1950 के 10% से बढ़ कर 2050 में अनुमानतः वैश्विक निर्गत का 40% होगा

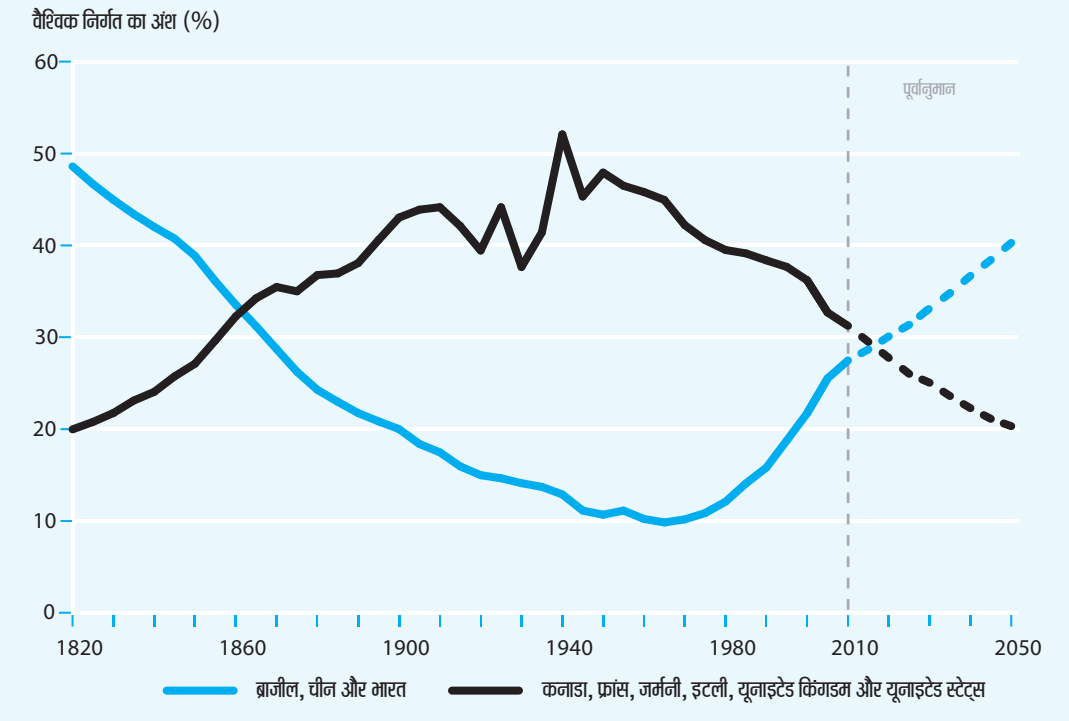

नोटः निर्गत को 1990 में क्रय शक्ति समता डालरों में मापा गया है।
स्रोतः मैडिसन (2010) से लिए आँकड़ों से मा.वि.सू. का आन्तरगणन (interpolation) और पार्डी सेन्टर फॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स (2013) के पूर्वानुमानों के आधार पर।

है। विश्व भर में स्वास्थ्य और शिक्षा की असमानता में पिछले दो दशकों में आय की तुलना में ज्यादा कमी आई है (रेखांकन 4)। लगभग सारे अध्ययन सहमत हैं कि वैश्विक आय असमानता ऊँची है, हालाँकि इन रुझानों पर सर्वानुमति नहीं है।

एक अधिक वैश्विक दक्षिण

वैश्विक उत्पादन पिछले 150 वर्षों में कभी न देखे गए तरीकों से पुनर्संतुलित हो रहा है। साधनों, सेवाओं, लोगों और विचारों के सीमा-पार आवागमन में वृद्धि उल्लेखनीय रही है। 2011 तक व्यापार का विश्व उत्पादन में हिस्सा लगभग 60% हो चुका था। विकासशील देशों ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है (बॉक्स 2)—1980 और 2010 के बीच उन्होंने व्यापारिक माल के विश्व व्यापार में अपना हिस्सा 25% से बढ़ाकर 47% कर लिया और वैश्विक उत्पादन में अपना हिस्सा 33% से बढ़ाकर 45% कर लिया। विकासशील क्षेत्र एक दूसरे के साथ भी संपर्क मज़बूत करते रहे हैं: 1980 और 2011 के बीच दक्षिण-दक्षिण व्यापार विश्व वाणिज्य व्यापार के 8.1% हिस्से से 26.7% हो गया (रेखांकन 5)।

दक्षिण के उदय में अभी सभी विकासशील देश सम्मिलित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, 49 सबसे कम विकसित देशों में, विशेषतः जो स्थलरुद्ध (landlocked) हैं या विश्व बाज़ारों से दूर हैं, परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत धीमी है। फिर भी, इनमें से कई देशों ने दक्षिण-दक्षिण व्यापार, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी अंतरण (transfer) का फ़ायदा उठाना शुरु कर दिया है। मिसाल के तौर पर, चीन से काफ़ी सकारात्मक प्रगति दूसरे विकासशील देशों पर छलकी है, खास तौर पर उसके करीबी व्यापार भागीदारों में। इन फ़ायदों ने किसी हद तक विकसित देशों से घटती माँग की क्षतिपूर्ति की है। अगर चीन और भारत में विकसित देशों की तरह ही संवृद्धि गिरी होती तो निम्न-आय देशों में 2007-2010 के दौरान आर्थिक संवृद्धि अनुमानतः 0.3-1.1 प्रतिशत बिन्दु कम रही होती।

वृद्धि के छलकाव (spill overs) से कई देशों ने भी मानव विकास में योगदान करने वाले क्षेत्रकों में फ़ायदा उठाया है, विशेषतः स्वास्थ्य में। उदाहरण के लिए, भारतीय कंपनियाँ सस्ती दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, और सूचना व संचार तकनीक संबंधी उत्पाद और सेवाएँ अफ्रीकी देशों को बेच रही हैं। ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की कंपनियाँ यही काम अपने क्षेत्रीय बाज़ारों में कर रही हैं।

फिर भी, बड़े देशों से निर्यात के नुकसान भी हो सकते हैं। बड़े देश लघुतर देशों में ऐसे प्रतिस्पर्धी दबाव पैदा कर सकते हैं जिनसे आर्थिक विविधीकरण और औद्योगीकरण अवरुद्ध हो जाएँ। वहीं, ऐसे उदाहरण भी हैं जहाँ प्रतिस्पर्धी झटकों के बाद औद्योगिक पुनर्जीवन हुआ है। आज की प्रतिस्पर्धी भूमिका कल आसानी से सम्पूरक भूमिका में बदल सकती है। प्रतिस्पर्धा से सहयोग तक पहुँचना नई चुनौतियों से निपटने की नीतियों पर निर्भर करता है।

रेखांकन 3

दक्षिण में मध्यम वर्ग के बढ़ते रहने के अनुमान हैं

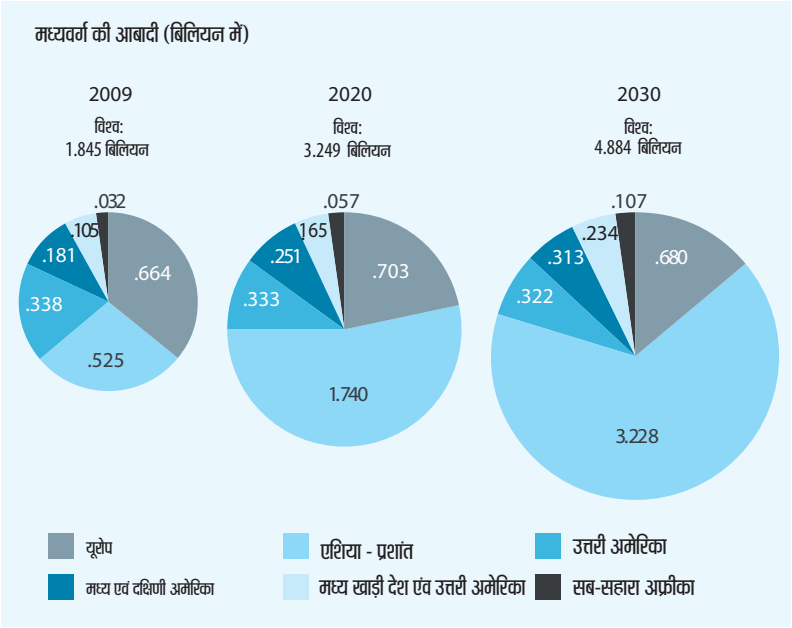

नोटः मध्यम वर्ग में शामिल हैं (डालर) 10-100 प्रतिदिन कमाने या खर्चने वाले लोग (2005 में क्रय शक्ति समता के आधार पर)
स्रोतः ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन 2012।

विकास रूपान्तरण के प्रचालक

बहुत से देशों ने पिछले दो दशकों में ठोस प्रगति की है: दक्षिण का उदय खासा व्यापक रहा है। इतना ही नहीं, कई ऊँचे प्रदर्शन वाले देशों ने न केवल राष्ट्रीय आय बढ़ाई, बल्कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों पर भी औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है।

दक्षिण के इतने सारे देशों ने कैसे अपनी मानव विकास संभावनाएँ रूपांतरित की हैं? अधिकांशतया इन देशों में विकास के तीन उल्लेखनीय प्रचालक (drivers) रहे हैं: एक सक्रिय विकासपरक राज्य, वैश्विक बाज़ारों का उपयोग और सकल्पशील (determined) सामाजिक नीति व नवाचार। ये प्रचालक तत्व, विकास को कैसे काम करना चाहिए, इसकी अमूर्त परिकल्पनाओं से नहीं लिए गए हैं, बल्कि वे दक्षिण के बहुत से देशों के रूपांतरकारी विकास अनुभवों द्वारा साकार दिखाए गए हैं। सच तो यह है कि वे पूर्वधारित (pre conceived) और आदेशात्मक दृष्टिकोणों को चुनौती देते हैं: एक ओर वे कई समूहवादी, केन्द्रीय प्रबंधित निर्देशों को किनारे करते हैं, दूसरी ओर वे वाशिंगटन सर्वानुमति द्वारा प्रतिपादित निर्बाध उदारीकरण से अलग राह अपनाते हैं।

दक्षिण के उदय में अभी सभी विकासशील देश सम्मिलित नहीं हैं

एक मनुष्य होना क्या होना है?

लगभग आधी सदी पहले, दार्शनिक टॉमस नागेल ने एक प्रसिद्ध लेख प्रकाशित किया, शीर्षक था 'एक चमगादड़ होना क्या होना है?' जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ वह है: एक मनुष्य होना क्या होना है? दरअसल, टॉम नागेल का दि फिलॉसॉफिकल रिव्यू में छपा अंतर्दृष्टिपूर्ण लेख भी मनुष्यों के बारे में ही था, और अंशतः ही चमगादड़ों के बारे में। दूसरे बिन्दुओं के अलावा, नागेल ने गहरी आलोचना व्यक्त की निरीक्षणवादी वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति एक चमगादड़ होने– या इसी तरह एक मनुष्य होने– के अनुभव की पहचान मस्तिष्क और शरीर में दूसरी जगहों पर होने वाली उन भौतिक परिघटनाओं से करने की आदत से, जिनका बाहरी निरीक्षण आसान है। एक चमगादड़ या एक मनुष्य होने का बोध सिर्फ मस्तिष्क और शरीर में चन्द चिह्नकों के होने जैसा नहीं हो सकता। मस्तिष्क की जटिलता शरीर की सरलतर निरीक्षणीयता से नहीं सुलझाई जा सकती (भले ही ऐसा करने का प्रलोभन कितना हो)।

मानव विकास दृष्टिकोण की प्रगतिशीलता भी एक अंतर पर आधारित है– लेकिन नागेल की बुनियादी ज्ञानशास्त्रीय विपरीतता से अलग तरह के अंतर पर। वह दृष्टिकोण जो महबूबुल हक़ ने 1990 में शुरु हुई मानव विकास रिपोर्टों के माध्यम से आगे बढ़ाया था। यह दृष्टिकोण जहाँ एक ओर मनुष्य जीवनों की समृद्धि का आकलन कठिन समस्या है, जिसमें शामिल हैं वे आज़ादियाँ जो मनुष्य के लिए मूल्यवान हैं, और दूसरी ओर वे सरल तरीके जिनसे आमदनियों और दूसरे बाहरी संसाधन– जो लोगों और देशों के पास होते हैं– की जानकारी रखी जा सकती है। सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) को देखना और नापना लोगों के मानवीय जीवन की गुणवत्ता को नापने से कहीं आसान है। लेकिन मानव कल्याण और स्वतंत्रता तथा उनके संसार की निष्पक्षता और न्याय से अंतर्संबंध को स.घ.उ. और उसकी वृद्धि दर तक सीमित नहीं किया जा सकता, जैसा बहुत से लोग करने को लालायित होते हैं।

मानव विकास की अंतर्निहित जटिलता को स्वीकारना ज़रूरी है, अंशतः तो इसलिए कि हमें उस प्रश्न को बदलने की ओर न सरका दिया जाए जो महबूबुल हक की साहसी पहल का केन्द्रीय बिन्दु था– स.घ.उ. का सम्पूरण (supplement) और किसी हद तक विस्थापन। लेकिन उसके साथ एक ज्यादा कठिन बिन्दु भी आया– जिसे हम मानव विकास दृष्टिकोण कहते हैं, जो उसका एक अभिन्न अंग है। सुविधा के लिए हम मानव विकास के कई आसान संकेतकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मा.वि.सू., जो केवल तीन परिवर्तों (variables) के प्रयोग और उन्हें आनुपतिक महत्व देने के एक बहुत आसान नियम पर आधारित है। किन्तु खोज वहाँ खत्म नहीं होती। हमें इन पर उपयोगी और कामचलाऊ तरीकों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए– स.घ.उ. की तुलना में मा.वि.सू. से मानव जीवन की गुणवत्ता के विषय में कहीं अधिक जानकारी प्राप्त हो सकती है– परंतु हमें एक सतत प्रयास वाले विश्व में इन कामचलाऊ रास्तों से मिलने वाले त्वरित लाभ से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। जीवन की गुणवत्ता को मापना एक अत्यंत जटिल कार्य है– बनिस्पत मात्र एक अंक (number) माध्यम से व्यक्त होने वाली उस वास्तविकता के, चाहे उसे मापने के लिए शामिल किए गए परिवर्तों को बहुत जाँच-परख के बाद तय किया गया और उन परिवर्तों को आनुपातिक महत्व देने की प्रक्रिया कितनी ही निष्पक्ष क्यों न हो।

इस जटिलता को स्वीकारने के अन्य महत्वपूर्ण निहितार्थ भी हैं। जटिलता को मान्यता देने के कारण ही, भले ही अंशतः, सार्वजनिक तर्क की महत्वपूर्ण भूमिका भी पनपती है– जिस पर वर्तमान मानव विकास रिपोर्ट विशेष जोर देती है। यह सही है कि जूता कहाँ काट रहा है, यह तो पहनने वाला ही बता सकता है, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि जूता काटने से बचाने वाली व्यवस्थाएँ तब तक प्रभावशाली नहीं बन सकती, जब तक लोगों को अपनी बात कहने और सार्वजनिक चर्चा करने के व्यापक अवसर नहीं दिए जाएँ। लोगों की खुशहाली और स्वतंत्रता का मूल्यांकन करने वाले विभिन्न घटकों के महत्व की समझ तथा उसका आकलन केवल और केवल आबादी के साथ ऐसे सतत संवाद के माध्यम से सम्भव है, जिस संवाद का सार्वजनिक नीति-निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव हो। तथाकथित अरब क्रान्ति और विश्व के किसी भी जन आंदोलन के राजनीतिक महत्व की तुलना आम लोगों की उन अभिव्यक्तियों और पारस्परिक संवादों से की जा सकती है जिसमें वे अपने जीवन के कष्ट-अड़चनों को दूसरों से कहते हैं और यह भी कि कौन से अन्यायों को वे दूर करना चाहते हैं। विचार-विमर्श करने को बहुत कुछ है– एक-दूसरे के साथ और नीति निर्माण करने वाले लोक सेवकों के साथ भी।

जब शासन के विभिन्न स्तरों को संवाद की जिम्मेदारियों का ठीक से अहसास हो जाता है, तो इसमें ऐसे लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व भी अनिवार्यतया शामिल होना चाहिए जो स्वयं अपनी ज़रूरतों को अपनी आवाज़ में व्यक्त करने के लिए यहाँ अभी उपस्थित नहीं हैं। मानव विकास भावी पीढ़ी के सराकारों के प्रति केवल इसलिए उदासीन नहीं हो सकता कि वर्तमान में उसकी उपस्थिति नहीं है। पर मनुष्य में दूसरों के, उनके जीवन के बारे में सोचने की क्षमता होती है। और एक जिम्मेदार व जवाबदेह राजनीति से अपेक्षित है कि वह संकीर्ण, आत्मकेन्द्रित सरोकारों में उलझे संवादों से भिन्न, सामाजिक समझ को विस्तार देकर भविष्यत और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं और स्वतंत्रताओं को महत्व दे। यहाँ बात केवल इन समस्त सरोकारों को एक अकेले सूचक में समाहित करने की नहीं है– जैसे कि पहले से ही भारी-भरकम हो चुके मा.वि.सू. पर (जोकि वैसे भी केवल वर्तमान खुशहाली और आज़ादी का सूचक है) और बोझ लाद दिया जाए। असल मुद्दा है यह सुनिश्चित करना कि मानव विकास की चर्चाओं में उन दूसरे चिंता-सरोकारों को भी शामिल किया जाए। मानव विकास रिपोर्टें फलक विस्तार की इस प्रक्रिया में योगदान देने का सिलसिला जारी रख सकती हैं– व्याख्या-विश्लेषणों तथा प्रासंगिक जानकारियों की सारणियों के जरिए।

मानव विकास का दृष्टिकोण, मानव जीवन की सफलताओं और वंचितताओं को समझने की कठिन प्रक्रिया में हुई अहम प्रगति का परिचायक है, साथ ही यह परिचायक है गहन आत्मनिरीक्षण तथा संवाद की महत्ता का– और इसके माध्यम से दुनिया में निष्पक्षता और न्याय के उन्नयन का। हम एक बात में काफ़ी हद तक चमगादड़ों के समान हो सकते हैं कि उनकी ही तरह एक अधीर पर्यवेक्षण विज्ञानी की मापक छड़ की पकड़ से बचे रहें, लेकिन चमगादड़ों से बहुत आगे जाकर हममें यह क्षमता होती है कि हम अपने और दूसरों के बहु-आयामी जीवनों के वर्तमान और भविष्य के बारे में बात करें और सोच सकें। इसलिए इन्सान होना एक स्तर पर तो चमगादड़ जैसा होना है लेकिन उससे बहुत भिन्न होना भी है।

प्रचालक 1- प्रसक्रिय विकासपरक राज्य

एक मज़बूत, प्रसक्रिय (pro active) और ज़िम्मेदार राज्य सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के लिए नीतियाँ विकसित करता है– एक दीर्घावधि दृष्टि और नेतृत्व, साझा सिद्धांतों और मूल्यों, तथा ऐसे नियमों और संस्थाओं के आधार पर, जो भरोसा और सुसंगति बनाते हैं। स्थाई रूपांतरण हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि देश विकास के प्रति एक संगत और संतुलित रास्ता अपनाएँ। जिन देशों ने आय और मानव विकास में टिकाऊ वृद्धि जगाने में सफलता हासिल की है, उन्होंने कोई एक सरल नुस्खा नहीं अपनाया। अलग-अलग चुनौतियों के सामने उन्होंने बाज़ार नियमन, निर्यात प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास और तकनीकी अनुकूलन तथा प्रगति के अलग-अलग रास्ते अपनाए हैं। ज़रूरी है कि वरीयताएँ जन-केन्द्रित हों, जो गिराव के जोखिमों से लोगों को बचाते हुए अवसरों को बढ़ावा दें। सरकारें ऐसे उद्योगों को पोषित कर सकती हैं जो अपूर्ण बाज़ारों के कारण अन्यथा न

रेखाकंन 4

अधिकांश क्षेत्रक आय में बढ़ती असमानता और स्वास्थ्य व शिक्षा में घटती असमानता दिखाते हैं

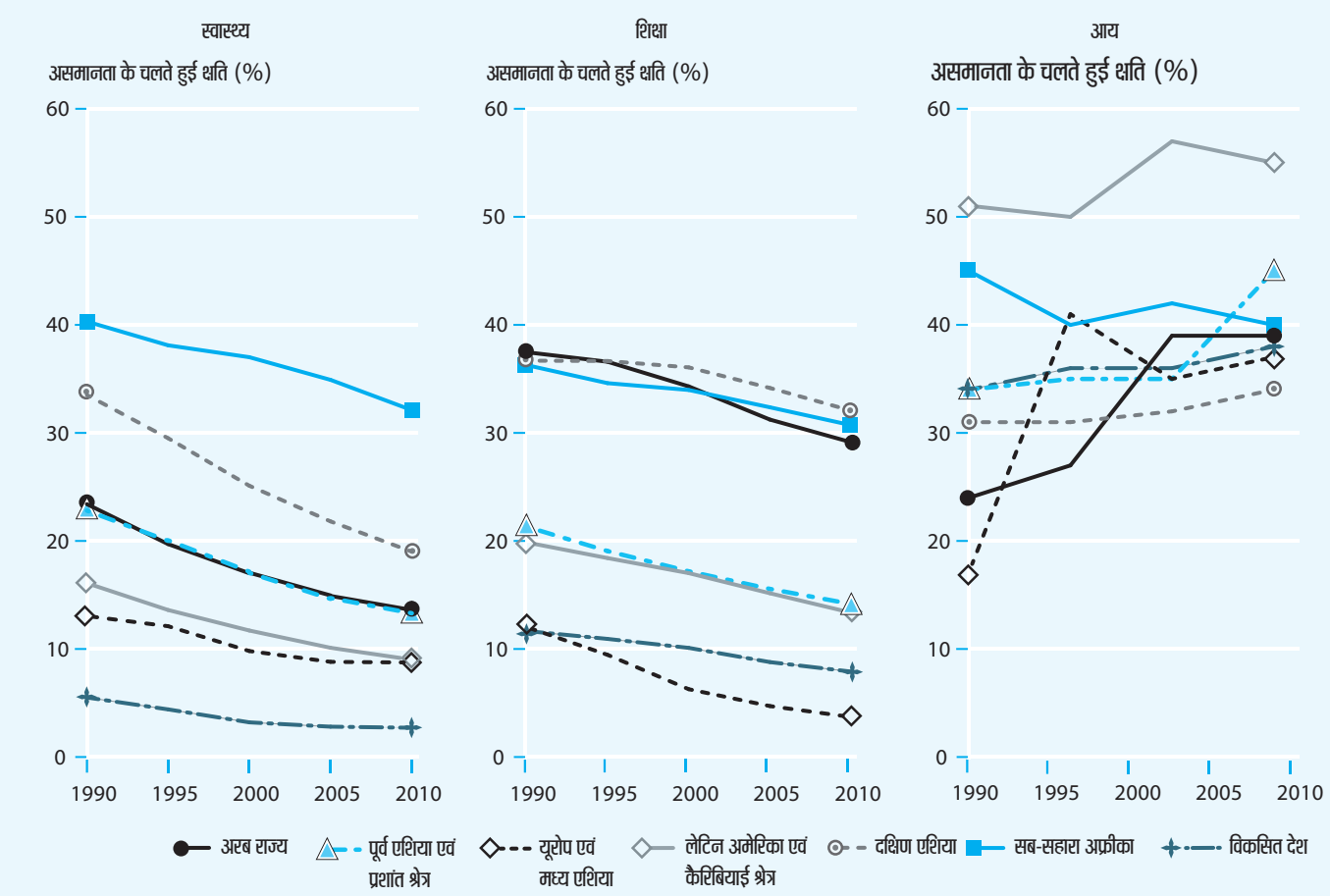

नोटः स्वास्थ्य असमानता के कारण हानि के लिए 182 देशों, शिक्षा असमानता के कारण हानि के 144 देशों, और आय असमानता के कारण हानि के 66 देशों के जनसंख्या-भारित संतुलित पैनल के आधार पर। आय असमानता पर मिलानोविक (2010) के आँकड़े 2005 तक उपलब्ध हैं।

स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ युनाइटेड नेशन्स डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनोमिक एंड सोशल अफ़ेयर्स की लाइफ़ टेबल से प्राप्त स्वास्थ्य आँकड़ों, बैरो एंड ली (2010) से शिक्षा आँकड़ों, और मिलानोविक (2010) से आय असमानता आँकड़ों के प्रयोग के आधार पर।

उभर सकेंगे। हालाँकि इसमें अनुचित लाभ उठाने और पक्षपात जैसे राजनीतिक जोखिम रहते हैं, इसने दक्षिण के कई देशों के ऐसे उद्योगों को सफल निर्यात के लिए सक्षम बनाया है, जिन्हें पहले अकार्यक्षम कह दिया जाता था। ऐसा तब हुआ, जब उनकी अर्थव्यवस्थाएँ ज्यादा मुक्त हुईं।

विशाल और जटिल समाजों में किसी भी नीति का परिणाम अनिवार्य तौर पर अनिश्चित होता है। विकासमूलक राज्यों के लिए व्यावहारिक होना, और विभिन्न रास्तों का परीक्षण करना ज़रूरी होता है। कुछ तत्व साफ़-साफ़ दिखाई देते हैंः उदाहरण के लिए, जन-समर्थक विकासमूलक राज्यों ने बुनियादी सामाजिक सेवाओं का विस्तार किया है। लोगों की क्षमताओं में निवेश करना– स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी सामाजिक सेवाओं के माध्यम से– विकास प्रक्रिया का एक अतिरिक्त तत्व नहीं, उसका अविभाज्य हिस्सा है (रेखांकन 7 और 8)। अच्छे रोज़गारों का तेज़ विस्तार मानव विकास बढ़ाने वाली संवृद्धि का एक अहम तत्व है।

प्रचालक 2- वैश्विक बाज़ारों का दोहन

वैश्विक बाज़ारों ने प्रगति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी नए औद्योगीकृत होते देशों ने ''बाकी दुनिया जो जानती है, उसका आयात और जो वह चाहती है, उसका निर्यात'' की रणनीति अपनाई है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इन बाज़ारों से जुड़ने की शर्तें। लोगों पर निवेश किए बिना वैश्विक बाज़ारों के मिलने वाले फ़ायदे सीमित ही रहेंगे। सफलता अपनी अर्थव्यवस्था को अचानक खोल देने के नहीं, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्रमिक और चरणबद्ध तरीके से एकीकरण का

बॉक्स 2

दक्षिण का विश्व-अर्थव्यवस्था से एकीकरण और मानव विकास

अवधि 1990-2010 के बीच 107 चुने हुए विकासशील देशों में से कोई 87% वैश्विक अर्थव्यवस्था से एकीकृत माने जा सकते हैं: उन्होंने अपना व्यापार-निर्गत अनुपात बढ़ाया है, उनकी कई ठोस व्यापारिक साझेदारियाँ हैं।[1] और उन्होंने समतुल्य आय स्तर वाले देशों की तुलना में उच्च व्यापार-निर्गत अनुपात बनाए रखा है।[2] ये सभी विकासशील देश एक-दूसरे से और विश्व से अधिक जुड़े हुए हैं: इंटरनेट का उपयोग बड़े पैमाने पर विस्तारित हुआ है, 2000 से 2010 के बीच उपयोगकर्ताओं की संख्या में माध्य वार्षिक वृद्धि 30% से अधिक रही है।

यद्यपि वैश्विक रूप से एकीकृत सभी विकासशील देशों ने मानव विकास सूचकांकों में तेज़ वृद्धि अर्जित नहीं की है, तथापि इसका विपर्यय (converse) सत्य है। लगभग वे सभी देश (इन चुनिंदा देशों में से कम से कम 45) जिन्होंने मानव विकास सूचकांकों में 1990 से 2012 के बीच अपने अन्य समकक्षों की तुलना में सबसे अधिक सफलता हासिल की है, पिछले दो दशक में विश्व अर्थव्यवस्था से सबसे अधिक एकीकृत हुए हैं। उनके व्यापार-उत्पादन अनुपात में विकासशील देशों के समूह से लगभग 13% अधिक वृद्धि हुई तथा उनका मानव विकास सूचकांकों पर बेहतर प्रदर्शन है। यह उन पिछले निष्कर्षों के अनुरूप है कि जैसे-जैसे देश विकसित होते हैं, वे अधिक खुलते जाते हैं।[3]

मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.) में महत्वपूर्ण सुधार के साथ तेज़ी से एकीकृत हो रहे देशों में केवल वे ही बड़े देश शामिल नहीं हैं जो सुर्ख़ियों में छाये रहते हैं, बल्कि इसमें दर्जनों छोटे और अल्प विकसित देश भी शामिल हैं। इस तरह वे अक्सर सुने जाने वाली परिवर्णी शब्दावली (acronyms) ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूसी महासंघ, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), आई.बी.एस.ए. (भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका), सी.आई.वी.ई.टी.एस. (कोलंबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, मिस्र, तुर्की और दक्षिण अफ्रीका) और मिस्ट (मेक्सिको, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका [कोरिया गणराज्य] और तुर्की) जैसे संदर्भित किये जाने वाले समूहों वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक विविध और बड़ा समूह बनाते हैं। नीचे दिया हुआ चित्र सूचक है व्यापार-निर्गत अनुपात के वैश्विक बाज़ार में भागीदारी की गहनता का, जो संदर्भ में मानव विकास सूचकांक के परिवर्तनों[4] को प्रदर्शित करता है। वर्ष 1990 से 2012 के बीच इन विकासशील देशों में से 80% से अधिक ने अपना व्यापार-निर्गत अनुपात बढ़ाया। इस उपसमूह के उन अपवादों में, जिन्होंने अपना मानव विकास सूचकांक भी महत्वपूर्ण रूप से सुधारा है, तीन बड़े देश (इंडोनेशिया, पाकिस्तान और वेनेज़ुएला) हैं, जो विश्व बाज़ार में वैश्विक भागीदार माने जाते हैं और कम से कम 80 देशों से आयात-निर्यात करते हैं। दो छोटे देश, जिनका व्यापार-निर्गत अनुपात घटा (मारीशस और पनामा) अब भी उन स्तरों से काफ़ी ऊँचे स्तर पर व्यापार कर रहे हैं जिसकी उनके समतुल्य आय-स्तर वाले अन्य देशों से अपेक्षा की जाती है। ऐसे सभी देश जिन्होंने 1990 से 2012 के बीच मा.वि.सू. में उल्लेखनीय सुधार किया है और अपना व्यापार-उत्पादन अनुपात बढ़ाया है, चित्र के ऊपर दायीं ओर के चतुर्थांश (quadrant) में चिन्हित किये गए हैं। नीचे दाईं ओर के चतुर्थांश में वे देश हैं जिन्होंने अपना व्यापार-उत्पादन अनुपात तो बढ़ाया, लेकिन मानव विकास सूचकांक में मामूली विकास किया, इनमें केन्या, फ़िलीपीन्स और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

दक्षिण में मानव प्रगति एवं व्यापार विस्तार

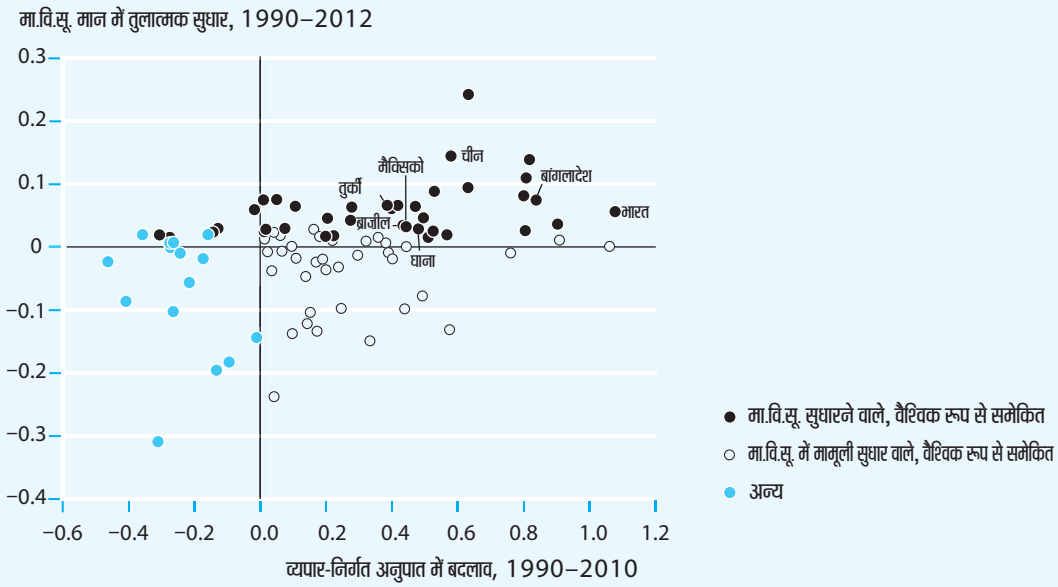

1. द्विपक्षीय व्यापार 2010-2011 में 2 मिलियन डॉलर को पार कर गया।
2. प्रति व्यक्ति आय पर व्यापार-स.घ.उ. अनुपात, जो भू-रुद्धता व जनसंख्या को नियंत्रित करता है, के लिए अंतर्देशीय समाश्रयण के परिणामों पर आधारित।
3. देखें रोड्रिक (2001)।
4. सापेक्षिक मा.वि.सू. की गणना 1990 से 2012 के बीच मा.वि.सू. के मानों के लघुगणकों (log) में परिवर्तन के 1990 के आरंभिक मा.वि.सू. पर समाश्रयण के अवशिष्ट से की जाती है। ऊपर के बाएँ चतुर्थांश में काले रंग से इंगित किए पाँच देश वे हैं जहाँ मा.वि.सू.मान में अहम सुधार हुए हैं, लेकिन उनके यहाँ 1990 से 2010 के बीच व्यापार-उत्पादन अनुपात घटा है, फिर भी उन्होंने या तो वैश्विक स्तर पर कई ठोस व्यापारिक संबंध बनाए या समतुल्य स्तर के प्रतिव्यक्ति आय वाले देशों से पूर्वानुमान से अधिक व्यापार किया। ऊपर दायें और नीचे दायें चतुर्थांश में खाली गोलों से इंगित किए गए देशों ने 1990 से2012 के बीच सापेक्षिक मानव विकास सूचकांक मान में ठीक-ठीक काम किया है, लेकिन या तो व्यापार-निर्गत औसत को बढ़ाया है या फिर बड़ी संख्या में ठोस व्यापारिक संबंध बनाए रखे हैं।

स्रोत: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ, व्यापार-उत्पादन अनुपात के आँकड़े विश्व बैंक से (2012a)।

परिणाम होती है, ऐसा एकीकरण जो राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार हो और लोगों, संस्थाओं और अवसंरचना में निवेश के साथ किया गया हो। लघुतर अर्थव्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक ऐसे विशिष्ट उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित किया है जो मौजूदा दक्षताओं या नई दक्षताओं के निर्माण को वर्षों के राज्य-समर्थन का परिणाम होते हैं।

प्रचालक 3- संकल्पशील सामाजिक नीति नवाचार

कम ऐसे देश हैं जिन्होंने बिना प्रभावशाली सार्वजनिक निवेश के टिकाऊ बढ़त हासिल की है– न सिर्फ़ अवसंरचना में बल्कि शिक्षा, और स्वास्थ्य में भी। लक्ष्य होना चाहिए ऐसे लाभकारी चक्र बनाना जिनमें संवृद्धि और सामाजिक नीतियाँ एक-दूसरे को पुष्ट करें। संवृद्धि अक्सर उच्च आय असमानता वाले देशों की तुलना में निम्न आय असमानता वाले देशों में ग़रीबी घटाने में ज्यादा प्रभावी रही है। समानता को प्रोत्साहित करना, विशेषकर विभिन्न धार्मिक, जातीय और नस्ली समूहों में भी, सामाजिक संघर्ष घटाने में मदद करता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी सशक्तीकरण और सामाजिक संगठन– सब ग़रीब लोगों को संवृद्धि में सहभागी बनने में सक्षम बनाते हैं। विभिन्न क्षेत्रकों में संतुलन– खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान– और रोज़गार विस्तार की प्रकृति और गति यह तय करने में अहम हैं कि संवृद्धि आमदनियों को कितना फैलाती है। लेकिन हो सकता है ये बुनियादी नीतियाँ भी वंचित, उपेक्षित वर्गों को सशक्त न कर पाएँ। समाज के हाशियों पर रहते ग़रीबों को अपनी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और सरकारें हमेशा यह नहीं देख पातीं कि सबके लिए तय सेवाएँ उन तक पहुँच रही हैं कि नहीं। सामाजिक नीति को समावेशन बढ़ाना चाहिए– भेदभावविहीनता और समान व्यवहार सुनिश्चित करना राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए केन्द्रीय हैं– और बुनियादी सामाजिक सेवाओं को मुहैया कराना चाहिए जो एक स्वस्थ, शिक्षित श्रमिक बल के उदय को सहारा देकर दीर्घावधि आर्थिक विकास को आधार दे। ज़रूरी नहीं कि ऐसी सारी सेवाएँ सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही उपलब्ध कराई जाएँ। लेकिन यह ज़रूरी है कि राज्य सुनिश्चित करे कि मानव विकास की मूलभूत ज़रूरतों तक सारे नागरिकों की पक्की पहुँच हो (बॉक्स 3 देखें)।

इस तरह, मानव विकास को बढ़ावा देने वाले विकास रूपांतरण का एजेंडा बहुआयामी है। यह आधारभूत सेवाओं तक पहुँच को सार्वभौम बना कर लोगों की परिसंपत्तियों का विस्तार करता है। यह राजकीय और सामाजिक संस्थाओं की कार्यशैली को सुधार कर समतापूर्ण विकास को बढ़ाता है, जहाँ फ़ायदे सुविस्तृत होते हैं। यह आर्थिक क्रिया और सामाजिक गतिशीलता पर प्रशासनिक और

रेखांकन 5

विश्व वस्तु व्यापार के हिस्से के रूप में दक्षिण-दक्षिण व्यापार 1980-2011 में तिगुने से ज्यादा हो गया, जबकि उत्तर-उत्तर व्यापार घटा

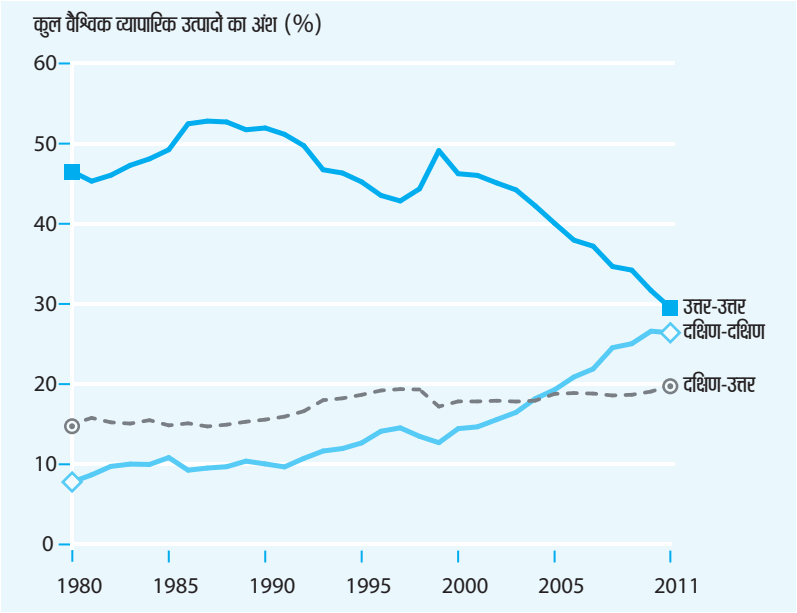

नोट: 1980 के (में) उत्तर में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, न्यू ज़ीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप शामिल हैं।
स्रोत: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ, यू.एन.एस.डी. (2012) पर आधारित।

रेखांकन 6

कुछ देशों ने मा.वि.सू. के ग़ैर-आय और आय, दोनों आयामों में अच्छा प्रदर्शन किया

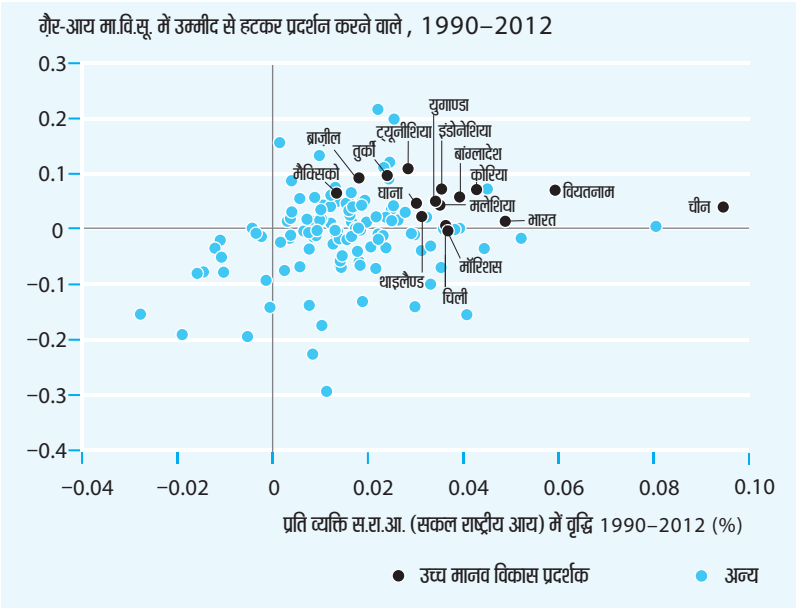

नोट: 96 देशों के संतुलित पैनल पर आधारित।
स्रोत: एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ।

रेखाकंन 7

वर्तमान मा.वि.सू. मान और पिछले सार्वजनिक खर्च का सकारात्मक अंतर्संबंध है...

स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ और विश्व बैंक (2012a).

रेखाकंन 8

...वैसे ही जैसे वर्तमान में बाल उत्तरजीविता और स्वास्थ्य पर पूर्ववर्ती सार्वजनिक खर्च में अंतर्संबंध

स्रोतः विश्व बैंक (2012a) पर आधारित एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ

सामाजिक बन्धनों को कम करता है। और यह नेतृत्व को जवाबदेह बनाता है।

संवेग को बनाए रखना

दक्षिण के बहुत से देशों ने काफ़ी सफलता दिखाई है। लेकिन उच्च प्रदर्शन वाले देशों में भी भविष्य की सफलता की गारंटी नहीं है। दक्षिण के देश कैसे मानव विकास में अपनी प्रगति की गति को बनाए रखें, और यह प्रगति कैसे दूसरे देशों तक पहुँचाई जा सकती है? रिपोर्ट इसके लिए चार महत्वपूर्ण क्षेत्र सुझाती हैः समता का विस्तार, लोगों की अभिव्यक्ति और सहभागिता बढ़ाना, पर्यावरणीय दबावों का सामना और जनसांख्यिकीय बदलाव को साधना। रिपोर्ट नीति निष्क्रियता की ऊँची कीमत की ओर इशारा करती है और उच्चतर महत्वाकांक्षी नीतियों की पैरवी करती है।

समता का विस्तार

वृहत्तर समता, पुरुषों और स्त्रियों तथा वर्गों के बीच, केवल अपने आपमें ही मूल्यवान नहीं है, बल्कि मानव विकास बढ़ाने के लिए अनिवार्य है। इस उद्देश्य के लिए सबसे शक्तिशाली ज़रिया है शिक्षा जो लोगों के आत्म-विश्वास को मज़बूत करती है और उनके लिए बेहतर रोज़गार ढूँढना, सार्वजनिक विमर्श में शामिल होना और सरकार से स्वास्थ्य सेवाएँ, सामाजिक सुरक्षा और दूसरे अधिकार माँगना आसान बनाती है।

शिक्षा के स्वास्थ्य और मृत्युदर पर भी जबर्दस्त प्रभाव हैं (बॉक्स 4)। रिपोर्ट के लिए किया गया शोध बताता है कि बाल उत्तरजीविता (child survival) घरेलू आमदनी या समृद्धि से ज्यादा माँ की शिक्षा पर निर्भर है, और जहाँ शैक्षिक उपलब्धियाँ शुरु में कमज़ोर हों, वहाँ नीतिगत दखल ज्यादा प्रभावकारी होती हैं। इसके गहरे नीतिगत निहितार्थ हैं, जो हमारा और सरकारों का ध्यान घरेलू आमदनी बढ़ाने की कोशिशों से हटाकर लड़कियों की शिक्षा सुधारने के उपायों पर ले जाते हैं।

यह रिपोर्ट नीतिगत महत्वाकांक्षा की सशक्त वकालत करती है। त्वरित प्रगति के परिदृश्य के अनुसार निम्न मा.वि.सू. वाले देश उच्च एवं अति उच्च मा.वि.सू. वाले देशों द्वारा प्राप्त किए गए मानव विकास के स्तर की ओर अभिमुख हो सकते हैं। सन् 2050 तक, सब-सहारा अफ्रीका में कुल मा.वि.सू. 52% बढ़ सकता है (0.402 से 0.612 तक) और दक्षिण एशिया में 36 फ़ीसदी (0.527 से 0.714)। इस परिदृश्य के तहत ग़रीबी के खिलाफ़ लड़ने में नीतिगत हस्तक्षेपों का भी सकारात्मक असर होगा। इसके विपरीत, निष्क्रियता की कीमत लगातार बढ़ती जाएगी, खासकर 7 अधिक अरक्षित निम्न मा.वि.सू. वाले देशों में। उदाहरण के लिए, सार्वभौम शिक्षा की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में असफल रहने पर आने वाली

बॉक्स 3

माइकेल ब्लूमबर्ग, मेयर, न्यूयॉर्क शहर

ग़रीबी उन्मूलन की नीति के कारगर सुझाव की खोज में न्यूयॉर्क ने दक्षिण का रुख क्यों किया

न्यूयॉर्क शहर में हम अपने नागरिकों का जीवन बेहतर करने के लिए कई तरीकों से काम कर रहे हैं। हम लगातार अपने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। धूम्रपान और मोटापा घटाकर हमने न्यूयॉर्क वासियों के स्वास्थ्य को बेहतर किया है। अलग साइकिल पथ बनाकर और लाखों पेड़ लगाकर हमने शहर के परिदृश्य को सुधारा।

ग़रीबी घटाने की कोशिश में हमने आत्मनिर्भरता के नए और बेहतर तरीकों की खोज की और अपने युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास किया है। इस प्रयास को सही ढंग से आगे ले चलने के लिए हमने सेंटर फ़ॉर इकोनॉमिक ऑपरच्यूनिटी की स्थापना की। इस केन्द्र का उद्देश्य ऐसी रणनीतियों की पहचान करना है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के क्षेत्र में नवाचारी पहलों के माध्यम से ग़रीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकें।

पिछले छह वर्षों के दौरान इस केन्द्र ने शहर के अभिकरणों और सैंकड़ों सामुदायिक संगठनों से साझीदारी करके 50 से भी अधिक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किए हैं। केन्द्र ने प्रत्येक प्रायोगिक कार्यक्रम के लिए एक विशिष्ट मूल्यांकन रणनीति विकसित की है, उनकी प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है, प्रत्येक प्रायोगिक कार्यक्रम के परिणामों की तुलनात्मक समीक्षा की जा रही है और इसका आकलन किया जा रहा है कि कौन सी रणनीतियाँ ग़रीबी घटाने तथा विकल्पों का विस्तार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। सफल साबित होने वाले कार्यक्रमों को सार्वजनिक और निजी धन की मदद से आगे भी जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। असफल कार्यक्रमों को रोक दिया जाता है और उनसे बचे संसाधनों को दूसरी रणनीतियों के लिए निवेशित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया से मिलने वाले निष्कर्षों को फिर सरकारी अभिकरणों, नीति निर्माताओं, ग़ैर-सरकारी साझीदारों और निजी दानदाताओं समेत देश और दुनिया के उन सहयोगियों से साझा किया जाता है जो हमारी ही तरह ग़रीबी के दुष्चक्र को तोड़ने के नए तरीकों की खोज में लगे हैं।

न्यूयॉर्क भाग्यशाली है कि दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वालों में से कुछ लोग उसके विश्वविद्यालयों और व्यापार जगत में काम कर रहे हैं, फिर भी हमें अहसास है कि दुनिया के और हिस्सों में विकसित हुए कार्यक्रमों से भी बहुत कुछ सीखने को है। इसी वजह से केन्द्र ने अपना काम शुरू करते समय ग़रीबी हटाने की संभावनायुक्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रणनीतियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण करवाया था।

वर्ष 2007 में अमेरिका में पहली बार *ऑपरच्यूनिटी न्यूयॉर्क सिटी: फ़ैमिली रिवार्ड्स* नाम से नकदी अंतरण का कार्यक्रम शुरू किया। बीस से भी अधिक देशों में चल रहे ऐसे ही कार्यक्रमों के आधार पर शुरू किए गए फ़ैमिली रिवार्ड्स पहल में ग़रीबी घटाने के लिए परिवारों को रोग निवारण सेवा अपनाने, शिक्षा और नौकरी संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहक दिए जाते हैं। फ़ैमिली रिवार्ड का खाका तैयार करते समय हमने ब्राज़ील, मैक्सिको और दर्जनों अन्य देशों के अनुभवों से मदद ली। अपने तीन साल के प्रायोगिक कार्यक्रम का अंत आते-आते हम यह समझ चुके थे कि कार्यक्रम के कौन से तत्व न्यूयॉर्क शहर के लिए काम के थे और कौन से नहीं– और यह ऐसी जानकारी है जो अब सारी दुनिया में ऐसे नए कार्यक्रमों की समूची पीढ़ी के लिए मददगार है।

ऑपरच्यूनिटी न्यूयॉर्क सिटी: फ़ैमिली रिवार्ड्स को शुरू करने से पहले, मैं मैक्सिको के तोलूका में गया ताकि समझ सकूँ कि मैक्सिको के सशर्त नकदी हस्तांतरण कार्यक्रम ऑपरच्यूनिडेड्स की सफलता की वजह क्या है। हमने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित उत्तर-दक्षिण 'लर्निंग एक्सचेंज कार्यक्रम' में भी भाग लिया। हमने लैटिन अमेरिका, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में चलने वाले सशर्त नकदी हस्तांतरण कार्यक्रमों के बारे में अनुभवों का साझा कर रॉकेफ़ेलर फ़ाउंडेशन, विश्व बैंक, ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ़ अमेरिकन स्टेट्स के अलावा अन्य संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय नीति-निर्माताओं के साथ मिलकर काम किया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखने-सिखाने का हमारा ये 'लर्निंग एक्सचेंज' आयोजन केवल नकदी अंतरण पहलों तक ही सीमित नहीं रहा, शहरी यातायात से संबंधित नवाचारी तरीकों को, शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली नई पहलों तथा अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी इसी तरह के आदान-प्रदान के कार्यक्रम इसमें शामिल हैं।

बेहतर विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं होता, और इसीलिए न्यूयॉर्क दूसरे शहरों तथा देशों में होने वाले श्रेष्ठ कार्यों से सीखना जारी रखेगा। और नए कार्यक्रमों को अपने शहर के हिसाब से ढालने तथा उनका मूल्यांकन करने के साथ ही साथ, हम संकल्पबद्ध हैं कि इस सीख का लाभ दुनिया भर के समुदायो के जीवन में स्थायी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करें।

पीढ़िओं के लिहाज से मानव विकास के कई अनिवार्य और आधारभूत आयाम बुरी तरह प्रभावित होंगे।

अभिव्यक्ति और सहभागिता का सबलीकरण

जब तक आम आदमी की उन कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं में अर्थपूर्ण तरीके से भागीदारी नहीं होती जो उनके जीवन को आकार देती हैं, तब तक राष्ट्रीय मानव विकास के मार्ग न तो वांछित होंगे और न ही टिकाऊ। आम आदमी को नीति निर्धारण व परिणामों को प्रभावित करने में समर्थ होना चाहिए और युवाओं को बेहतर आर्थिक अवसरों और राजनीति में सहभागिता और जवाबदेही की आशा रखनी चाहिए।

उत्तर और दक्षिण, दोनों ही क्षेत्रों मे असंतोष बढ़ रहा पर है क्योंकि लोग अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त करने और नीतियों को प्रभावित करने के लिए अधिक अवसर चाहते हैं, खासतौर पर आधारभूत सामाजिक सुरक्षा को लेकर। प्रदर्शनकारियों में युवा सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, कुछ अंशों में यह रोज़गार की कमी और शिक्षित युवकों के लिए नौकरियों के सीमित अवसरों के कारण है। उदासीन-असंवेदनशील सरकारों के खिलाफ़ लोकप्रिय विद्रोहों से इतिहास भरा पड़ा है। असंतोष से निवेश में रुकावटें आती हैं और मानव विकास में बाधा उत्पन्न होती है और निरंकुश सरकारें संसाधनों का रुख कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की ओर मोड़ देती हैं।

ऐसी कोई भी भविष्यवाणी करना बेहद कठिन है कि समाज उस अ-पुनरावर्ती स्थिति (tipping point) में कब आयेंगे। जनांदोलनों के, विशेषतौर पर शिक्षित लोगों द्वारा, तभी भड़कने की आशंका होती है जब यह लगने लगे कि राजनीतिक प्रयासों में व्यय की गई ऊर्जा के मुकाबले आर्थिक अवसरों की सम्भावनाएँ बहुत क्षीण हैं। इस तरह की 'प्रयत्न-सघन राजनीतिक सहभागिता' तब आसानी से जनसंचार के नवीन स्वरूपों के माध्यम से सूत्रबद्ध और एकजुट हो जाती है।

यह रिपोर्ट नीतिगत महत्वाकांक्षा की सशक्त वकालत करती है

रेखाकंन 9

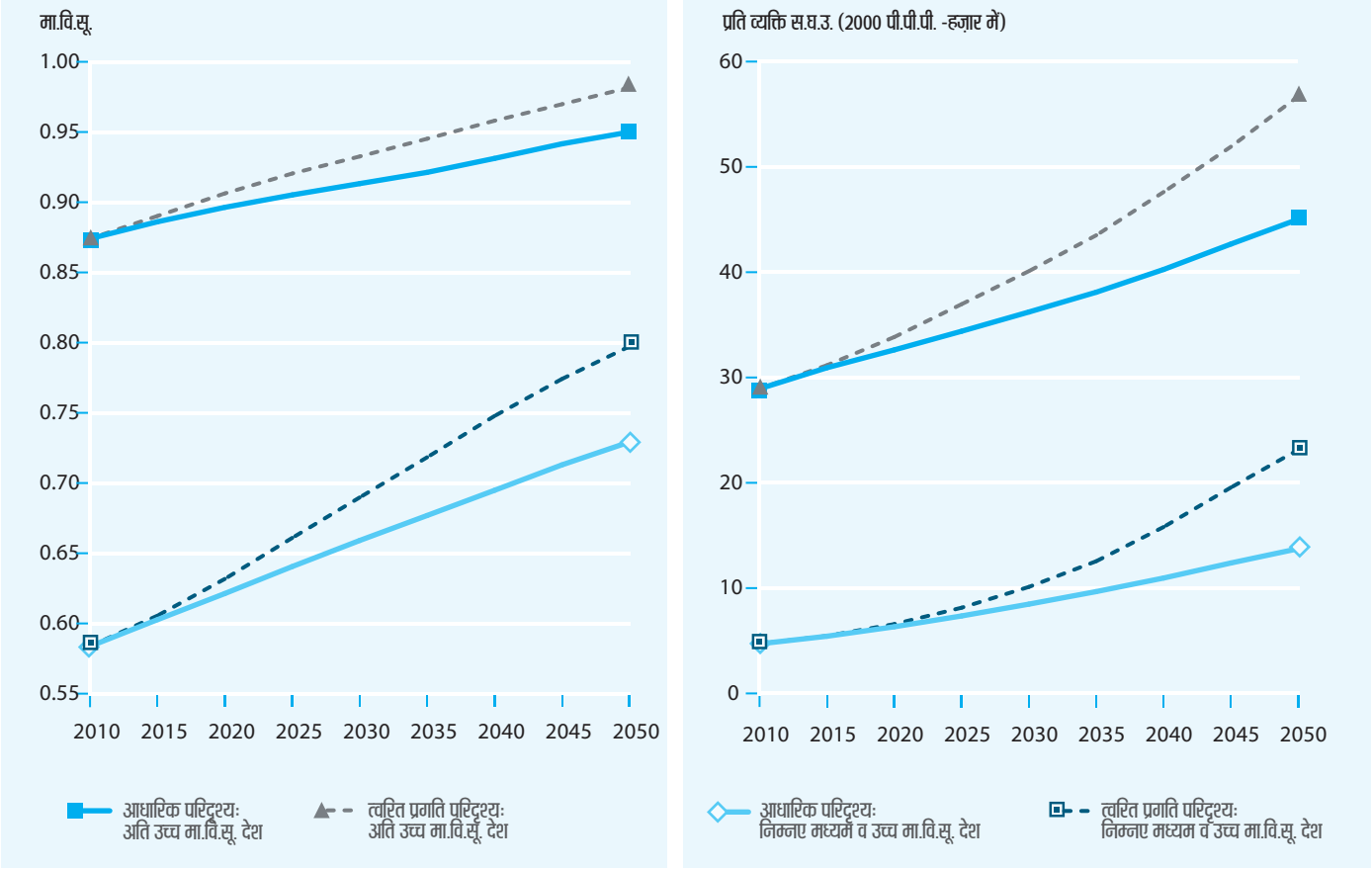

मानव विकास के लिहाज से देखें तो निम्न मा.वि.सू. मान वाले देशों के लिए निष्क्रियता की तुलनात्मक कीमत ज्यादा होगी। प्रति व्यक्ति स.घ.उ. में होने वाली क्षति के लिहाज से निष्क्रियता की कीमत देशों के लिए आनुपातिक रूप से एकसमान रहेगी, उनके मा.वि.सू. के स्तर से इसपर कोई असर नहीं पड़ेगा।

स्रोतः एच.डी.आर.ओ. गणनाएँ, पार्डी सेंटर फ़ॉर इंटरनेशनल फ्यूचर्स के आधार पर (2013).

पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना

वैसे तो पर्यावरणीय खतरे, जैसे जलवायु परिवर्तन, निर्वनीकरण, जल व वायु प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएँ सभी को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये ग़रीब देशों और ग़रीब समुदायों के लिए सबसे ज्यादा दुखदायी होते हैं। जलवायु परिवर्तन पहले से ही गम्भीर पर्यावरणीय खतरों को बदतर बना रहा है और पारिस्थितिकीय तंत्र को होने वाली हानि आजीविका के अवसरों को संकुचित कर रही है, खासतौर पर ग़रीबों के लिए।

यद्यपि निम्न मा.वि.सू. देशों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन में अल्पतम योगदान होता है, परन्तु वार्षिक वर्षा में कमी की सबसे ज्यादा मार झेलने की संभावना उन्हीं की होती है और वार्षिक वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता का सबसे तीखा दंश भी वही झेलते हैं– इससे आजीविका और कृषि उत्पादन गम्भीर रूप से प्रभावित होते हैं। इस तरह के भारी-भरकम नुकसान इस ज़रूरत को बेहद तीखे रूप से रेखांकित करते हैं कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लोच-बल से लोगों को लैस करने की तत्काल आवश्यकता है।

ऐसी आशंका है कि निष्क्रियता की कीमत बहुत अधिक होगी। कार्यवाही को जितना ही टाला जाएगा, कीमत उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। संवहनीय अर्थव्यवस्थाओं व समाजों की सुनिश्चिति के लिए ऐसी नई नीतियों और ढाँचागत परिवर्तनों की ज़रूरत है जो मानव विकास तथा जलवायु परिवर्तन के उद्देश्यों की संगति निम्न उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन-सक्षम रणनीतियों और नवाचारी सार्वजनिक-निजी वित्तीयन कार्यप्रणालियों के साथ बिठा कर आगे बढ़ सकें।

जनसांख्यिकीय बदलावों का प्रबंधन

1970 से 2011 के मध्य में दुनिया की आबादी 3.6 अरब से बढ़कर 7 अरब हो गई है। जैसे-जैसे दुनिया की आबादी में शिक्षा बढ़ेगी, वैसे-वैसे जनसंख्या विकास की दर घटेगी। आबादी की आयु संरचना और उसका आकार विकास की सम्भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इसीलिए वह एक मुद्दा जो लगातार बढ़ती चिन्ता का सबब बना हुआ है, वह है निर्भरता अनुपात– यानी युवाओं और वृद्धों

बॉक्स 4

कोरिया गणतंत्र और भारत में जनसंख्या की सम्भावनाओं में भिन्नता की गुंजाइश क्यों

कोरिया गणतंत्र में शैक्षिक स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। सन् 1950 में जहाँ स्कूल जाने की आयु के बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करता था, वहीं आज युवा कोरियाई महिलाएँ दुनिया की सबसे शिक्षित महिलाएँ हैं; आधे से अधिक ने महाविद्यालय स्तर की शिक्षा पूर्ण कर ली है। इसके परिणामस्वरूप, भविष्य के कोरियाई बुज़ुर्ग आज के कोरियाई बुज़ुर्गों के मुकाबले अधिक शिक्षित होंगे (आँकड़े देखें), और शिक्षा व स्वास्थ्य में सकारात्मक सह-संबंध होने के कारण उनके अधिक स्वस्थ होने की भी सम्भावना है।

यह मानते हुए कि नामांकन की दर (जो अभी बहुत अधिक है) स्थिर रहेगी, 14 वर्ष से कम आयु की आबादी का अनुपात 2010 के 16 प्रतिशत के मुकाबले 2050 में गिर कर 13 प्रतिशत रह जायेगा। आबादी की शैक्षिक संरचना में भी उल्लेखनीय परिवर्तन होगा, उच्च स्तर की शिक्षा का अनुपात 26 से बढ़ कर 47 प्रतिशत होने का अनुमान है। भारत के लिए, परिदृश्य बहुत अलग दिखता है। सन् 2000 से पहले, आधी से अधिक वयस्क जनसंख्या को कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी। हाल ही में प्राथमिक शिक्षा में हुए विस्तार और बेहतर शिक्षा प्राप्त भारतीयों की संख्या में प्रभावी वृद्धि (निस्संदेह इसका प्रमुख कारण हाल का आर्थिक विकास है) के बावजूद औपचारिक शिक्षा प्राप्त न कर सकने वाले वयस्कों का अनुपात बहुत धीमी गति से कम हो रहा है। कुछ हद तक शिक्षा के इस निम्न स्तर का कारण, खासतौर पर महिलाओं में, भारत की जनसंख्या के तेज़ी से बढ़ने का अनुमान है, और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन को पीछे छोड़ देगा। बहुत ही आशावादी त्वरित गति परिदृश्य में भी, जिसमें कोरिया की भाँति शैक्षिक विस्तार हो, तो भी 2050 में भारत का शैक्षिक परिदृश्य बहुत ही असमान होगा, जिसमें अशिक्षित वयस्कों (अधिकांशतः वृद्ध) का प्रतिशत बहुत अधिक होगा। हालाँकि इस परिदृश्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तेज़ी से विस्तार के चलते, बहुत शिक्षित युवा वयस्कों के श्रम बल का निर्माण होगा।

कोरिया गणतंत्र तथा भारत की आबादी व शिक्षा का तुलनात्मक भविष्य

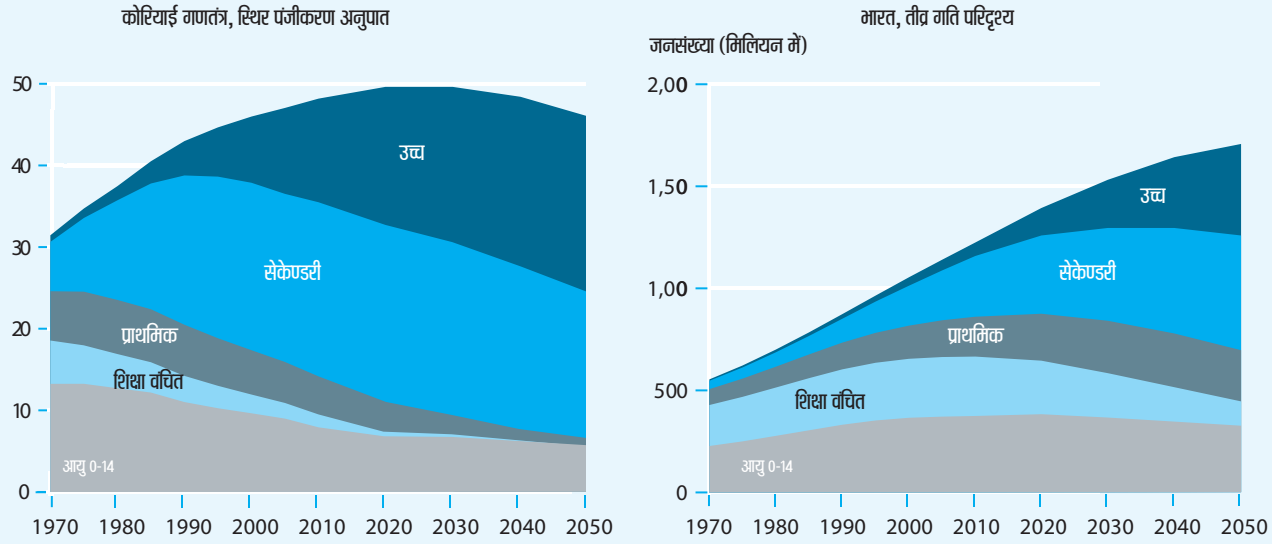

स्रोत : लुत्ज व के.सी. 2013

की कुल संख्या को 15-64 वर्ष की कार्यशील आयु वालों की जनसंख्या से भाग देने पर मिली संख्या।

अगर काम करने वाली आबादी का कुल जनसंख्या में हिस्सा बढ़ता है तो कुछ ग़रीब देशों को जनसांख्यिकीय लाभांश का फ़ायदा मिलेगा– लेकिन तभी जब वहाँ मज़बूत नीतिगत पहल हो। उदाहरण के लिए, लड़कियों की शिक्षा किसी भी सम्भावित जनसांख्यिकीय लाभांश के लिए एक अहम वाहक होता है। शिक्षित महिलाएँ कम बच्चे पैदा करने की मानसिकता वाली होती हैं, उनके बच्चे स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बेहतर होते हैं; अनेक देशों में शिक्षित महिलाओं को अशिक्षित मज़दूरों से बेहतर वेतन मिलता है।

इसके विपरीत, दक्षिण के धनवान क्षेत्रों में जैसे-जैसे उनकी आबादी की उम्र बढ़ेगी, उन्हें एक अलग ही समस्या का सामना करना पड़ेगा– कार्यशील आयु वालों का कुल आबादी में घटता अनुपात। आबादी के बुज़ुर्ग होने की दर का विशेष महत्व है, क्योंकि विकासशील देशों को अपनी बुज़ुर्ग आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद करनी ही होगी, अगर वे ग़रीब ही रह गए हैं, तो। अनेक विकासशील देशों के पास जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा फ़ायदा उठाने के अवसर अब बहुत ही सीमित हैं।

हालाँकि, जनसांख्यिकीय रुझान एकदम निश्चयात्मक नहीं होते। शिक्षा नीतियों के आधार पर कम से कम परोक्ष रूप से तो उन्हें बदला ही जा सकता है। यह रिपोर्ट 2010-2050 की अवधि के लिए दो परिदृश्य प्रस्तुत करती है: आधारिक परिदृश्य, जिसमें शिक्षा के हर स्तर पर पंजीकरण अनुपात स्थिर रहते हैं, और एक त्वरित गति परिदृश्य जिसमें आरम्भिक तौर पर न्यूनतम शिक्षा-स्तरों वाले देश महत्वाकांक्षी शैक्षिक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। इस त्वरित गति परिदृश्य के तहत

दक्षिण की बढ़ी हुई भागीदारी से कुछ आंतर-सरकारी स्तर की प्रक्रियाओं में जीवंतता आ जाएगी

निम्न मा.वि.सू. वाले देशों के निर्भरता अनुपात में आई कमी आधारिक परिदृश्य के तहत आई कमी के दोगुने से भी अधिक है। महत्वाकांक्षी शैक्षिक नीतियाँ मध्यम तथा उच्च मा.वि.सू. वाले देशों को उनके निर्भरता अनुपात के बढ़ने को लेकर किए गए पूर्वानुमानों को गलत साबित करने में सक्षम बना सकती हैं। और इस तरह एक बुजुर्ग आयु वाली आबादी के देश होने की ओर बढ़ते उनके कदमों को थाम कर उनकी दिक्कतें कुछ कम कर सकती हैं।

इन जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने के लिए एक ओर तो शैक्षिक उपलब्धि के स्तर में सुधार की ज़रूरत होगी, साथ ही उत्पादक रोज़गार के अवसरों का विस्तार करने की भी आवश्यकता होगी– बेरोज़गारी घटाकर, श्रम उत्पादकता को प्रोत्साहित करके तथा श्रम बल की भागीदारी बढ़ाकर, खासकर महिलाओं तथा उम्रदराज़ लोगों की।

नए दौर के लिए अधिशासन और साझेदारियाँ

विकासशील देशों द्वारा समर्थित नई व्यवस्थाएँ और तत्परिणामी बहुलता, कई बार सीधे और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से वैकल्पिक क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय प्रणालियों के माध्यम से बहुपक्षीयता के पारंपरिक प्रक्षेत्रों (domain)– वित्त, व्यापार, निवेश और स्वास्थ्य– की विद्यमान संस्थाओं और प्रक्रियाओं को चुनौती दे रही हैं। वैश्विक और क्षेत्रीय अधिशासन नई व्यवस्थाओं और पुरानी संरचनाओं का बहुरंगी मिश्रण बनता जा रहा है, जिसे कई तरीके से सामूहिक पोषण की आवश्यकता है। वैश्विक संस्थाओं में आंतरिक सुधार के काम में क्षेत्रीय संस्थाओं के साथ उनके सहयोग को पुष्ट किया जाना चाहिए, और कुछ मामलों में उन क्षेत्रीय संस्थाओं को, व्यापक अधिकार सम्पन्न करना चाहिए। संगठनों की जवाबदेही को राष्ट्रों के वृहत्तर समूह से जोड़ना चाहिए, और साथ ही साथ हितधारकों के वृहत्तर समूह से भी।

अनेक संस्थाएँ और अंतरराष्ट्रीय अधिशासन के सिद्धांत ऐसे हैं जो उस पुरानी दुनिया के लिए गढ़े गये थे, जिसका आज की समकालीन सच्चाई से तालमेल नहीं बैठता। इसका एक दुष्परिणाम यह है कि इन संस्थाओं में दक्षिण का प्रतिनिधित्व बेहद कम है। अगर इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को जीवित रहना है, तो फिर इन्हें अधिक प्रातिनिधिक, पारदर्शी और जवाबदेह होना होगा। यह तय है कि दक्षिण की बढ़ी हुई भागीदारी से कुछ अंतर-सरकारी स्तर की प्रक्रियाओं में जीवंतता आ जाएगी और इससे काफ़ी बड़ी मात्रा में वित्तीय, प्रौद्योगिकीय और मानव संसाधन जुट सकते हैं।

इन सभी से यह बात उभरती है कि सरकारें स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय सम्प्रभुता के संरक्षण को लेकर संवेदनशील हैं। फिर भी राष्ट्रीय सम्प्रभुता को लेकर कठोर रुख अपनाने से सीमा-पार प्रतिद्वंद्विता और सबके लिए नुकसानदेह विचारों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तरदायी सम्प्रभुता एक बेहतर रणनीति है, जिसके तहत विभिन्न देश एक साफ़-सुथरे, नियम आधारित और जवाबदेह अंतरराष्ट्रीय सहकार में संलग्न होते हैं और ऐसे सामूहिक प्रयासों में भागीदार होते हैं जिससे पूरी दुनिया के हितों को बढ़ावा मिले। ज़िम्मेदार सम्प्रभुता की दरकार यह भी है कि सरकारें अपने नागरिकों के स्वीकृत मानवाधिकारों का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस दृष्टि से सम्प्रभुता
एक अधिकार ही नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है।

इस बदलती हुई दुनिया में सार्वजनिक साधनों की उपलब्धता के लिए बहुत गहरे निहितार्थ हैं। अंतरराष्ट्रीय चिंता और सहकार का ध्यान जिन क्षेत्रों पर है, वे हैं व्यापार, प्रवास और जलवायु परिवर्तन। कुछ मामलों में सार्वजनिक साधन को क्षेत्रीय संस्थाओं के द्वारा भी उपलब्ध कराया जा सकता है, और इसके चलते उस ध्रुवीकरण की आशंका से बचा जा सकता है जो बड़े, बहुपक्षीय मंचों में प्रगति को धीमा कर देता है। लेकिन बढ़ते हुए क्षेत्रीय सहयोग की अपनी खामियाँ हो सकती हैं– इससे संस्थाओं के बहुस्तरीय, पहले से ही जटिलताओं वाले और खण्डित ताने-बाने की जटिलता और बढ़ सकती है। इसलिए एक सुसंगत बहुलता को सुनिश्चित करना ही चुनौती है– ताकि संस्थाएँ हरेक स्तर पर सामंजस्य के साथ काम कर सकें।

अंतरराष्ट्रीय अधिशासन संस्थाओं को न केवल सदस्य राष्ट्र, बल्कि वैश्विक नागर समाज भी जवाबदेह ठहरा सकता है। इन सामाजिक संस्थाओं ने वैश्विक स्तर पर दान, कर्ज़, मानवाधिकार, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के मसलों पर पारदर्शिता और नियम-निर्माण की प्रक्रियाओं को प्रभावित भी किया है। सामाजिक संस्थाओं का तंत्र अब नए संचार माध्यम और संचार तकनीक का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद सामाजिक संस्थाओं को भी अपनी वैधानिकता एवं जवाबदेही को लेकर सवालों का सामना करना पड़ता रहा है और इसके कई अवांछित रूप भी हो सकते हैं। फिर भी, अंतरराष्ट्रीय अधिशासन संस्थाओं की भविष्यत वैधानिकता संस्थाओं की नागरिक तंत्रों और समुदाओं के साथ तालमेल के साथ काम कर सकने की क्षमताओं पर निर्भर होगा।

निष्कर्षः नए दौर के साझीदार

दक्षिण के अनेक देशों ने कर दिखाया है कि मानव विकास का एक उत्पादक और संवहनीय तरीके से आगे बढ़ना सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन अभी भी उन्होंने केवल थोड़ा ही रास्ता तय किया है। आने वाले वर्षों के लिए यह रिपोर्ट मोटे तौर पर पाँच निष्कर्ष प्रस्तावित करती है:

दक्षिण की उभरती आर्थिक शक्ति के साथ ही मानव विकास के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए

मानव विकास में निवेश केवल नैतिक आधार पर ही औचित्यपूर्ण नहीं है, बल्कि इसलिए भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य में परिवर्तन और सामाजिक कल्याण में ज़रूरी

सुधार आज की अति स्पर्धात्मक और गतिशील विश्व अर्थव्यवस्था में सफलता की कुंजी हैं। इन क्षेत्रों में होने वाले निवेशों को खासकर ग़रीबों को लक्षित करना चाहिए– उन्हें बाज़ारों से जोड़ते हुए और आजीविका के अवसरों को बढ़ाते हुए। ग़रीबी एक ऐसा अन्याय है जिसे प्रतिबद्ध पहल के दम पर दूर किया जा सकता है और ऐसा होना ही चाहिए।

बेहतर नीति-निर्माण के लिए केवल निजी क्षमताओं पर ही नहीं, वरन सामाजिक क्षमताओं पर अधिक ध्यान देने की भी ज़रूरत होती है। सामाजिक संस्थाओं के दायरे में होने वाले वैयक्तिक काम लोगों के विकास की सम्भावनाओं को सीमित भी कर सकते हैं और विस्तारित भी। ऐसी नीतियाँ, जो इनसानों की सम्भावनाओं को सीमित करने वाले सामाजिक प्रचलनों को बदल देती हैं, जैसे छोटी उम्र में शादी या फिर दहेज के खिलाफ़ निर्णय, तो ऐसे बदलावों से लोगों को अपनी क्षमताओं को पूरा खिलने देने के अतिरिक्त अवसर मिल पाते हैं।

अल्प विकसित देश दक्षिण की उदीयमान आर्थिक शक्तियों की सफलता से सीख लेकर लाभान्वित हो सकते हैं

दक्षिण और उत्तर, दोनों ही वर्गों के देशों में जमा हुए अभूतपूर्व वित्तीय कोषों एवं सम्प्रभु निधियों (sovereign funds) ने एक व्यापक आधार वाली प्रगति को तेज़ी के अवसर उपलब्ध कराये हैं। इस जमापूँजी का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर मानव विकास एवं ग़रीबी उन्मूलन के लिए लगता है, तो उसका व्यापक असर हो सकता है। साथ ही, दक्षिण-दक्षिण के बीच होने वाला व्यापार और निवेश प्रवाह विदेशी बाज़ारों को एक नए तरीके से प्रभावित कर सकता है, जिससे विकास के अवसर बढ़ें, जैसे कि क्षेत्रीय और वैश्विक वैल्यू-चेनों में भागीदारी करके।

बढ़ता हुआ दक्षिण-दक्षिण व्यापार, और खासकर निवेश वह आधारभूमि तैयार कर सकता है जिसके चलते उत्पादन क्षमताओं को अन्य कम विकसित क्षेत्रों और देशों की ओर स्थानांतरित किया जा सके। हाल ही में शुरू हुए चीन और भारत के संयुक्त उपक्रमों और अफ्रीका में उत्पादन के लिए किए गए निवेशों ने एक बेहद विस्तृत आर्थिक बल की भूमिका तैयार कर दी है। अंतरराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्कों से अवसरों के वे नए द्वार खुले हैं जो उन्नत उत्पादन विधियों तक छलाँग लगाकर देशों की विकास प्रक्रियाओं को तेज़ कर सकते हैं।

नई संस्थाएँ और नई साझेदारियाँ क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण-दक्षिण रिश्तों की मज़बूती में सहायक हो सकती हैं

नई संस्थाएँ और साझेदारियाँ देशों को आपस में ज्ञान, अनुभव और प्रौद्योगिकी का साझा करने में मददगार हो सकती हैं। इसी के साथ-साथ समूचे दक्षिण में व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए तथा आपस में अनुभवों को बाँटने के लिए और नई व मज़बूत संस्थाएँ खड़ी की जा सकती हैं। इस दिशा में आगे बढ़ने का एक कदम हो सकता है एक नया दक्षिण आयोग जो दक्षिण की विविधता को इसकी एकजुटता की ताकत बनाने की ताज़ा दृष्टि लाए।

प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के समाधान की प्रगति में दक्षिण और नागर समाज की बढ़ी हुई भागीदारी से गति मिल सकती है

दक्षिण के उदय से विश्व मंच पर सुनाई दी जाने वाली आवाज़ों की विविधता बढ़ती जा रही है। इस बदलती परिस्थिति ने ऐसी अधिशासन संस्थाओं को बनाने के अवसर पैदा किए हैं जो उन सभी घटकों का पूरी तरह प्रतिनिधित्व कर सकें जो विश्व की समस्याओं का समाधान खोजने में इस विविधता का उत्पादक उपयोग कर सकें।

अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए ऐसे नए मार्गदर्शक सिद्धांतों की ज़रूरत है जिनमें दक्षिण के अनुभव भी शामिल हों। ग्रुप-20 का उदय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन दक्षिण के देशों को ब्रेटन वुड्स, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों में भी और समतापरक प्रतिनिधित्व दिए जाने की ज़रूरत है।

राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय नागर समाज और सामाजिक आंदोलन न्यायपूर्ण अधिशासन की अपनी माँग को बल देने में मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। इन आन्दोलनों तथा आम लोगों की आवाज़ों को दुनिया के सामने लाने वाले मंचों के लगातार हो रहे विस्तार ने अधिशासन संस्थाओं के सामने चुनौती पेश कर दी है कि वे अधिक लोकतांत्रिक व समावेशी सिद्धांतों को अपनाएँ। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि अधिक न्यायपरक और कमतर असमानता वाली दुनिया बनाने की दरकार यह है कि आवाज़ों की बहुलता के लिए जगह हो और लोक विमर्श के लिए एक कारगर तंत्र हो।

दक्षिण का उदय सार्वजनिक साधनों की बेहतर उपलब्धता के अवसर तैयार करता है

एक संवहनीय विश्व के लिए बेहतर अधिशासन और प्रचुर वैश्विक सार्वजनिक साधनों की उपलब्धता चाहिए। आज वैश्विक मसलों की संख्या और महत्व बढ़ रहा है– जलवायु परिवर्तन में कमी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक-वित्तीय अस्थिरता से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तथा नाभिकीय प्रसार तक। उनके लिए वैश्विक हल चाहिए। पर, अनेक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग धीमा और कई बार खतरनाक ढंग से हिचक भरा है। दक्षिण के उदय ने सार्वजनिक साधनों की बेहतर उपलब्धता

जमा हुए अभूतपूर्व वित्तीय कोष एक व्यापक आधार वाली प्रगति में तेज़ी के अवसर उपलब्ध कराते हैं

दक्षिण के उदय ने सार्वजनिक साधनों की बेहतर उपलब्धता और आज उलझ कर ठप पड़े अनेक वैश्विक मसलों को सुलझाने की नई सम्भावनाओं को जन्म दिया है

और आज उलझ कर ठप पड़े अनेक वैश्विक मसलों को सुलझाने की नई सम्भावनाओं को जन्म दिया है।

आमतौर पर 'सार्वजनिकता' और 'निज-पन' (privatness) सार्वजनिक साधनों की अंतर्जात प्रवृत्ति न होकर एक सामाजिक रचना है। ये एक तरह से नीतिगत विकल्प हैं। जब इनकी कमी हो, तब राष्ट्रीय सरकारें पहल कर उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं, पर जब वैश्विक चुनौतियाँ खड़ी हों, तब अंतरराष्ट्रीय सहकार आवश्यक होगा, और अनेक सरकारों की स्वैच्छिक क्रियाशीलता से ही ऐसा सम्भव होगा। अनेक आवश्यक चुनौतियों को ध्यान में रखकर यह तय करने के लिए कि क्या काम सार्वजनिक है और क्या निजी, एक मज़बूत, प्रतिबद्ध व्यक्तिगत और संस्थागत नेतृत्व की आवश्यकता होगी।

मानव विकास रिपोर्ट 2013 समकालीन वैश्विक संदर्भ को प्रस्तुत करती है और नीति-निर्माताओं तथा नागरिकों के लिए लगातार बढ़ती अंतर-सम्पृक्तता (interconnectedness) वाली इस दुनिया में राह बनाने तथा बढ़ती वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का पथ प्रशस्त करती है। आज की दुनिया में किस तरह सत्ता, सम्पत्ति और आवाज़ की गतिकियाँ (dynamics) बदल रही हैं, उनकी व्याख्या करते हुए यह रिपोर्ट उन नई अनिवार्य नीतियों और संस्थाओं को चिन्हित करती है, जो 21वीं सदी की इन चुनौतियों का सामना कर सकें तथा बेहतर समता, संवहनीयता व सामाजिक एकीकरण के साथ मानव विकास को प्रोत्साहित कर सकें। मानव विकास में प्रगति के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों स्तरों पर पहल और संस्थाओं की ज़रूरत है। वैश्विक स्तर पर संस्थागत सुधारों और नवाचारों की ज़रूरत है ताकि वैश्विक सार्वजनिक साधनों की उपलब्धता और संरक्षण सम्भव हो सके। और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है, वैसे ही, जैसे यह वास्तविकता कि देशों के संदर्भों, संस्कृतियों और संस्थागत परिस्थितियों की विविधता को ध्यान में रख कर 'सबके पैरों के लिए फ़िट है एक ही नंबर का जूता' वाली टैक्नोक्रेटिक नीतियाँ न तो यथार्थपरक होती हैं, न ही प्रभावी। फिर भी, सामाजिक संघटन (cohesion), शिक्षा-स्वास्थ्य-सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारों की प्रतिबद्धता जैसे अति महत्वपूर्ण और सर्व-समावेशी सिद्धांत और व्यापार के समेकन के लिए खुलापन– ये सब टिकाऊ और समतापरक मानव विकास की ओर बढ़ने के कारगर उपायों के रूप में उभरे हैं।

2012 की मा.वि.सू. श्रेणी और उसमें 2011 से 2012 के दौर में हुए उतार-चढ़ाव

अफ़गानिस्तान	175		
अल्बानिया	70	–1	↓
अल्जीरिया	93	–1	↓
अंडोरा	33	–1	↓
अंगोला	148		
एंटिगुआ एवं बरबूडा	67	–1	↓
अर्जेन्टीना	45	–1	↓
आर्मेनिया	87	–1	↓
ऑस्ट्रेलिया	2		
ऑस्ट्रिया	18		
अज़रबैजान	82	–1	↓
बहामास	49		
बहरीन	48		
बांग्लादेश	146	1	↑
बारबाडोस	38		
बेलारूस	50	1	↑
बेल्जियम	17		
बेलीज़	96		
बेनिन	166		
भूटान	140	1	↑
प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	108		
बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	81	–1	↓
बोत्स्वाना	119	–1	↓
ब्राज़ील	85		
ब्रुनेई दारस्सलाम	30		
बुल्गारिया	57		
बुर्किना फ़ासो	183		
बुरुण्डी	178	–1	↓
कंबोडिया	138		
कैमरून	150		
कनाडा	11	–1	↓
केप वर्दे	132	–1	↓
मध्य अफ़्रीकी गणराज्य	180	–1	↓
चाड	184		
चिली	40		
चीन	101		
कोलंबिया	91		
कॉमोरॉस	169	–1	↓
कॉन्गो	142		
कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य	186		
कोस्टा रिका	62		
आइवरी कोस्ट	168	1	↑
क्रोएशिया	47	–1	↓
क्यूबा	59		
साइप्रस	31		
चेक गणराज्य	28		
डेनमार्क	15		
जिबूती	164		
डोमिनिका	72		
डोमिनिकन गणराज्य	96	2	↑
इक्वाडोर	89		
इजिप्ट (मिस्र)	112		
अल सल्वाडोर	107	–1	↓
इक्वेटोरियल गिनी	136		
एरिट्रिया	181	1	↑
एस्टोनिया	33	1	↑
इथियोपिया	173	–1	↓
फ़िजी	96	2	↑
फ़िनलैंड	21		
फ़्रांस	20		
गैबन	106		
गैंबिआ	165		
जॉर्जिआ	72	3	↑
जर्मनी	5		
घाना	135		
ग्रीस	29		
ग्रेनाडा	63	–1	↓
ग्वाटेमाला	133		
गिनी	178	–1	↓
गिनी. बिसाउ	176		
गयाना	118	1	↑
हैती	161	1	↑
होण्डुरास	120		
हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	13	1	↑
हंगरी	37		
आइसलैंड	13		
भारत	136		
इण्डोनेशिया	121	3	↑
ईरान इस्लामिक गणराज्य	76	–2	↓
इराक	131	1	↑
आयरलैंड	7		
इस्राइल	16		
इटली	25		
जमैका	85	–2	↓
जापान	10		
जॉर्डन	100		
कज़ाकिस्तान	69	–1	↓
कीन्या	145		
किरिबाती	121		
कोरिया गणराज्य	12		
कुवैत	54	–1	↓
किर्गिस्तान	125		
लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	138		
लात्विया	44	1	↑
लेबनान	72		
लेसोथो	158	1	↑
लाइबेरिया	174		
लीबिया	64	23	↑
लिक्टन्सटाइन	24		
लिथुआनिया	41	2	↑
लक्ज़मबर्ग	26		
मैडागास्कर	151		
मलावी	170	1	↑
मलेशिया	64	1	↑
माल्दीव	104	–1	↓
माली	182	–1	↓
माल्टा	32	1	↑
मॉरितानिया	155		
मॉरिशस	80	–1	↓
मैक्सिको	61		
फेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	117		
माल्डोवा गणराज्य	113		
मंगोलिया	108	2	↑
मॉन्टीनेग्रो	52	–2	↓
मोरक्को	130		
मोज़ाबीक	185		
म्यॉंमार	149		
नामीबिआ	128		
नेपाल	157		
नीदरलैंड	4		
न्यूज़ीलैंड	6		
निकारागुआ	129		
नाइज़र	186	1	↑
नाइजीरिया	153	1	↑
नॉर्वे	1		
ओमान	84	–1	↓
पाकिस्तान	146		
पलाउ	52	2	↑
अधिकृत फ़लीस्तीनी क्षेत्र	110	1	↑
पनामा	59	1	↑
पापुआ न्यू गिनी	156		
पराग्वे	111	–2	↓
पेरू	77	–1	↓
फ़िलीपीन्स	114		
पोलैण्ड	39		
पुर्तगाल	43	–3	↓
कतर	36		
रोमानिआ	56	–1	↓
रूसी संघ (फ़ेडरेशन)	55		
रवाण्डा	167		
सेंट किट्स एवं नेविस	72	–1	↓
सेंट लूसिआ	88		
सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	83	–2	↓
समोआ	96		
साओ टोमे एवं प्रिन्साइप	144		
सउदी अरब	57		
सेनेगल	154	–2	↓
सर्बिआ	64		
सेशेल्स	46		
सिएरे लिओन	177	2	↑
सिंगापुर	18		
स्लोवाकिया	35		
स्लोवेनिया	21		
सॉलोमन द्वीप समूह	143		
दक्षिण अफ़्रीका	121	1	↑
स्पेन	23		
श्रीलंका	92		
सूडान	171	–1	↓
सूरीनाम	105		
स्वाज़ीलैंड	141	–1	↓
स्वीडन	7		
स्विटज़रलैण्ड	9		
सीरियाई अरब गणराज्य	116		
ताजिकिस्तान	125	1	↑
तन्ज़ानिआ संयुक्त गणराज्य	152	1	↑
थाइलैण्ड	103	1	↑
मेसाडोनियाए पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	78	–2	↓
टिमोर लेस्ट	134		
टोगो	159	1	↑
टोन्गा	95		
ट्रिनिडाड एवं टोबैगो	67	–1	↓
ट्यूनीशिया	94		
टर्की	90		
तुर्कमेनिस्तान	102		
युगाण्डा	161		
यूक्रेन	78		
संयुक्त अरब अमीरात	41	–1	↓
यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन)	26		
यूनाइटेड स्टेट्स (संयुक्त राज्य अमेरिका)	3	–1	↓
उरुग्वे	51		
उज़्बेकिस्तान	114	1	↑
वनुआतू	124	–2	↓
वेनेज़ूएला बोलिवेरियाई गणराज्य	71	–1	↓
वियतनाम	127		
येमन	160	–2	↓
ज़ाम्बिया	163		
ज़िबाब्वे	172	1	↑

नोट : तीर की दिशा 2011 से 2012 के बीच श्रेणी में देश के ऊपर अथवा नीचे खिसकने का सूचक है। सुसंगत आँकड़ों और कार्यविधियों के आधार पर, देश के आगे किसी सूचक तीर का अभाव उसकी यथास्थिति का द्योतक है।

मानव विकास सूचकांक

मा.वि.सू. श्रेणी	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.)	असमानता समायोजित मा.वि.सू.		लैंगिक असमानता सूचकांक		बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक	
	मान	मान	श्रेणी	मान	श्रेणी	मान	श्रेणी
अति उच्च मानव विकास							
1 नार्वे	0.955	0.894	1	0.065	5	..	
2 ऑस्ट्रेलिया	0.938	0.864	2	0.115	17	..	
3 यूनाइटेड स्टेट्स	0.937	0.821	16	0.256	42	..	
4 नीदरलैंड	0.921	0.857	4	0.045	1	..	
5 जर्मनी	0.920	0.856	5	0.075	6	..	
6 न्यूज़ीलैंड	0.919	..	..	0.164	31	..	
7 आयरलैंड	0.916	0.850	6	0.121	19	..	
8 स्वीडन	0.916	0.859	3	0.055	2	..	
9 स्विटज़रलैंड	0.913	0.849	7	0.057	3	..	
10 जापान	0.912	..	..	0.131	21	..	
11 कनाडा	0.911	0.832	13	0.119	18	..	
12 कोरिआ गणराज्य	0.909	0.758	28	0.153	27	..	
13 हांगकांग, चीन (एस.ए.आर.)	0.906	..	..	..	..	..	
14 आइसलैंड	0.906	0.848	8	0.089	10	..	
15 डेनमार्क	0.901	0.845	9	0.057	3	..	
16 इस्राइल	0.900	0.790	21	0.144	25	..	
17 बेल्जियम	0.897	0.825	15	0.098	12	..	
18 ऑस्ट्रिया	0.895	0.837	12	0.102	14	..	
18 सिंगापुर	0.895	..	..	0.101	13	..	
20 फ्रांस	0.893	0.812	18	0.083	9	..	
21 फ़िनलैंड	0.892	0.839	11	0.075	6	..	
22 स्लोवेनिया	0.892	0.840	10	0.080	8	0.000	2003
23 स्पेन	0.885	0.796	20	0.103	15	..	
24 लिख्टेन्स्टाइन	0.883	..	..	..	..	..	
25 इटली	0.881	0.776	24	0.094	11	..	
26 लक्ज़मबर्ग	0.875	0.813	17	0.149	26	..	
26 यूनाइटेड किंगडम	0.875	0.802	19	0.205	34	..	
27 चेक गणराज्य	0.873	0.826	14	0.122	20	0.010	2002/2003
29 यूनान	0.860	0.760	27	0.136	23	..	
30 ब्रूनेई दारस्सलाम	0.855	..	..	..	..	..	
31 साइप्रस	0.848	0.751	29	0.134	22	..	
32 माल्टा	0.847	0.778	23	0.236	39	..	
33 अंडोरा	0.846	..	..	..	..	..	
33 एस्टोनिआ	0.846	0.770	25	0.158	29	0.026	2003
35 स्लोवाकिआ	0.840	0.788	22	0.171	32	0.000	2003
36 कतर	0.834	..	..	0.546	117	..	
37 हंगरी	0.831	0.769	26	0.256	42	0.016	2003
38 बारबाडोस	0.825	..	..	0.343	61	..	
39 पोलैण्ड	0.821	0.740	30	0.140	24	..	
40 चिली	0.819	0.664	41	0.360	66	..	
41 लिथुएनिया	0.818	0.727	33	0.157	28	..	
41 संयुक्त अरब अमीरात	0.818	..	..	0.241	40	0.002	2003
43 पुर्तगाल	0.816	0.729	32	0.114	16	..	
44 लातीविया	0.814	0.726	35	0.216	36	0.006	2003
45 अर्जेंटीना	0.811	0.653	43	0.380	71	0.011	2005
46 सेशेल्स	0.806	..	..	..	..	..	
47 क्रोएशिया	0.805	0.683	39	0.179	33	0.016	2003
उच्च मानव विकास							
48 बहरीन	0.796	..	..	0.258	45	..	
49 बहामास	0.794	..	..	0.316	53	..	
50 बेलारूस	0.793	0.727	33	..	..	0.000	2005
51 उरुग्वे	0.792	0.662	42	0.367	69	0.006	2002/2003
52 मॉन्टीनेग्रो	0.791	0.733	31	..	..	0.006	2005/2006
52 पलाउ	0.791	..	..	..	..	..	
54 कुवैत	0.790	..	..	0.274	47	..	
55 रूसी गणराज्य	0.788	..	..	0.312	51	0.005	2003
56 रोमानिया	0.786	0.687	38	0.327	55	..	
57 बुल्गारिया	0.782	0.704	36	0.219	38	..	
57 सऊदी अरब	0.782	..	..	0.682	145	..	
59 क्यूबा	0.780	..	..	0.356	63	..	
59 पनामा	0.780	0.588	57	0.503	108	..	

	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.)	असमानता समायोजित मा.वि.सू.		लैंगिक असमानता सूचकांक		बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक	
मा.वि.सू. श्रेणी	मान	मान	श्रेणी	मान	श्रेणी	मान	श्रेणी
61 मैक्सिको	0.775	0.593	55	0.382	72	0.015	2006
62 कोस्टा रिका	0.773	0.606	54	0.346	62	..	
63 ग्रेनाडा	0.770	..	..	..	..	..	
64 लीबिया	0.769	..	..	0.216	36	..	
64 मलेशिया	0.769	..	..	0.256	42	..	
64 सर्बिया	0.769	0.696	37	..	..	0.003	2005/2006
67 एंटिगुआ और बरबूडा	0.760	..	..	..	..	..	
67 त्रिनिडाड टोबैगो	0.760	0.644	49	0.311	50	0.020	2006
69 कज़ाकिस्तान	0.754	0.652	44	0.312	51	0.002	2006
70 अल्बानिआ	0.749	0.645	48	0.251	41	0.005	2008/2009
71 वेनेज़ुएला बोलिवेरियाई गणराज्य	0.748	0.549	66	0.466	93	..	
72 डोमिनिका	0.745	..	..	..	..	..	
72 जॉर्जिआ	0.745	0.631	51	0.438	81	0.003	2005
72 लेबनान	0.745	0.575	59	0.433	78	..	
72 सेंट किट्स एवं नेविस	0.745	..	..	..	..	..	
76 ईरान इस्लामिक गणराज्य	0.742	..	..	0.496	107	..	
77 पेरु	0.741	0.561	62	0.387	73	0.066	2008
78 मेसाडोनिया पूर्ववर्ती यूगोस्लाव गणराज्य	0.740	0.631	51	0.162	30	0.008	2005
78 यूक्रेन	0.740	0.672	40	0.338	57	0.008	2007
80 मॉरिशस	0.737	0.639	50	0.377	70	..	
81 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना	0.735	0.650	45	..	..	0.003	2006
82 अज़रबैजान	0.734	0.650	45	0.323	54	0.021	2006
83 सेंट विन्सेन्ट एवं ग्रेनाडाइन	0.733	..	..	..	..	..	
84 ओमान	0.731	..	..	0.340	59	..	
85 ब्राज़ील	0.730	0.531	70	0.447	85	0.011	2006
85 जमैका	0.730	0.591	56	0.458	87	..	
87 अर्मेनिआ	0.729	0.649	47	0.340	59	0.001	2010
88 सेंट लूसिआ	0.725	..	..	..	..	..	
89 इक्वाडोर	0.724	0.537	69	0.442	83	0.009	2003
90 तुर्की	0.722	0.560	63	0.366	68	0.028	2003
91 कोलम्बिया	0.719	0.519	74	0.459	88	0.022	2010
92 श्रीलंका	0.715	0.607	53	0.402	75	0.021	2003
93 अल्जीरिया	0.713	..	..	0.391	74	..	
94 ट्यूनीशिया	0.712	..	..	0.261	46	0.010	2003
मध्यम मानव विकास							
95 टोंगा	0.710	..	..	0.462	90	..	
96 बेलीज़	0.702	..	..	0.435	79	0.024	2006
96 डोमीनिकन गणराज्य	0.702	0.510	80	0.508	109	0.018	2007
96 फ़िजी	0.702	..	..	..	..	..	
96 सामोआ	0.702	..	..	..	..	..	
100 जॉर्डन	0.700	0.568	60	0.482	99	0.008	2009
101 चीन	0.699	0.543	67	0.213	35	0.056	2002
102 तुर्कमेनिस्तान	0.698	..	..	..	..	..	
103 थाइलैंड	0.690	0.543	67	0.360	66	0.006	2005/2006
104 माल्दीव	0.688	0.515	76	0.357	64	0.018	2009
105 सूरीनाम	0.684	0.526	72	0.467	94	0.039	2006
106 गैबन	0.683	0.550	65	0.492	105	..	
107 अल सल्वाडोर	0.680	0.499	83	0.441	82	..	
108 प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ़ बोलिविया	0.675	0.444	85	0.474	97	0.089	2008
108 मंगोलिया	0.675	0.568	60	0.328	56	0.065	2005
110 फ़लस्तीन राज्य	0.670	..	..	..	..	0.005	2006/2007
111 परागवे	0.669	..	..	0.472	95	0.064	2002/2003
112 मिस्र	0.662	0.503	82	0.590	126	0.024	2008
113 माल्डोवा गणराज्य	0.660	0.584	58	0.303	49	0.007	2005
114 फ़िलीपीन्स	0.654	0.524	73	0.418	77	0.064	2008
114 उज़्बेकिस्तान	0.654	0.551	64	..	..	0.008	2006
116 सीरियाई अरब गणराज्य	0.648	0.515	76	0.551	118	0.021	2006
117 फ़ेडरेटेड स्टेट ऑफ़ माइक्रोनेशिया	0.645	..	..	..	..	..	
118 गुयाना	0.636	0.514	78	0.490	104	0.030	2009
119 बोत्स्वाना	0.634	..	..	0.485	102	..	
120 होण्डुरास	0.632	0.458	84	0.483	100	0.159	2005/2006
121 इण्डोनेशिया	0.629	0.514	78	0.494	106	0.095	2007

मा.वि.सू. श्रेणी	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.)	असमानता समायोजित मा.वि.सू.		लैंगिक असमानता सूचकांक		बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक	
	मान	मान	श्रेणी	मान	श्रेणी	मान	श्रेणी
121 किरिबाती	0.629	..	..	..	..	..	
121 दक्षिण अफ्रीका	0.629	..	..	0.462	90	0.057	2008
124 वनुआतू	0.626	..	..	..	..	0.129	2007
125 किर्गिस्तान	0.622	0.516	75	0.357	64	0.019	2005/2006
125 ताजिकिस्तान	0.622	0.507	81	0.338	57	0.068	2005
127 वियतनाम	0.617	0.531	70	0.299	48	0.017	2010/2011
128 नामीबिया	0.608	0.344	101	0.455	86	0.187	2006/2007
129 निकारागुआ	0.599	0.434	86	0.461	89	0.128	2006/2007
130 मोरक्को	0.591	0.415	88	0.444	84	0.048	2007
131 इराक	0.590	..	..	0.557	120	0.059	2006
132 केप वर्दे	0.586	..	..	..	..	..	
133 ग्वातेमाला	0.581	0.389	92	0.539	114	0.127	2003
134 टिमोर लेस्ट	0.576	0.386	93	..	..	0.360	2009/2010
135 घाना	0.558	0.379	94	0.565	121	0.144	2008
136 इक्वेटोरिअल गिनी	0.554	..	..	..	..	..	
136 भारत	0.554	0.392	91	0.610	132	0.283	2005/2006
138 कम्बोडिया	0.543	0.402	90	0.473	96	0.212	2010
138 लाओ जनतात्रिक गणराज्य	0.543	0.409	89	0.483	100	0.267	2006
140 भूटान	0.538	0.430	87	0.464	92	0.119	2010
141 स्वाज़ीलैण्ड	0.536	0.346	99	0.525	112	0.086	2010
निम्न मानव विकास							
142 कौंगो	0.534	0.368	96	0.610	132	0.208	2009
143 सॉलोमन द्वीपसमूह	0.530	..	..	..	..	..	
144 साओ टोम एवं प्रिन्साइप	0.525	0.358	97	..	..	0.154	2008/2009
145 केन्या	0.519	0.344	101	0.608	130	0.229	2008/2009
146 बांग्लादेश	0.515	0.374	95	0.518	111	0.292	2007
146 पाकिस्तान	0.515	0.356	98	0.567	123	0.264	2006/2007
148 अंगोला	0.508	0.285	114	..	..	..	
149 म्यॉंमार	0.498	..	..	0.437	80	..	
150 कैमरून	0.495	0.330	104	0.628	137	0.287	2004
151 मैडागास्कर	0.483	0.335	103	..	..	0.357	2008/2009
152 तंज़ानिया गणराज्य	0.476	0.346	99	0.556	119	0.332	2010
153 नाइजीरिया	0.471	0.276	119	..	..	0.310	2008
154 सेनेगल	0.470	0.315	105	0.540	115	0.439	2010/2011
155 मॉरिटानिया	0.467	0.306	107	0.643	139	0.352	2007
156 पापुआ न्यू गिनी	0.466	..	..	0.617	134	..	
157 नेपाल	0.463	0.304	109	0.485	102	0.217	2011
158 लेसोथो	0.461	0.296	111	0.534	113	0.156	2009
159 टोगो	0.459	0.305	108	0.566	122	0.284	2006
160 यमन	0.458	0.310	106	0.747	148	0.283	2006
161 हैती	0.456	0.273	120	0.592	127	0.299	2005/2006
161 युगाण्डा	0.456	0.303	110	0.517	110	0.367	2011
163 ज़ाम्बिया	0.448	0.283	117	0.623	136	0.328	2007
164 जिबूती	0.445	0.285	114	..	..	0.139	2006
165 गैम्बिया	0.439	..	..	0.594	128	0.324	2005/2006
166 बेनिन	0.436	0.280	118	0.618	135	0.412	2006
167 रवाण्डा	0.434	0.287	112	0.414	76	0.350	2010
168 आइवरी कोस्ट	0.432	0.265	122	0.632	138	0.353	2005
169 कोमोरॉस	0.429	..	..	..	..	..	
170 मलावी	0.418	0.287	112	0.573	124	0.334	2010
171 सूडान	0.414	..	..	0.604	129	..	
172 ज़िम्बाब्वे	0.397	0.284	116	0.544	116	0.172	2010/2011
173 इथियोपिया	0.396	0.269	121	..	..	0.564	2011
174 लाइबेरिया	0.388	0.251	123	0.658	143	0.485	2007
175 अफ़ग़ानिस्तान	0.374	..	..	0.712	147	..	
176 गिनी बिसाउ	0.364	0.213	127	..	..	..	
177 सिएरा लिओन	0.359	0.210	128	0.643	139	0.439	2008
178 बुरुण्डी	0.355	..	..	0.476	98	0.530	2005
178 गिनी	0.355	0.217	126	..	..	0.506	2005
180 मध्य अफ्रीकी गणराज्य	0.352	0.209	129	0.654	142	..	
181 इरिट्रिया	0.351	..	..	..	..	..	
182 माली	0.344	..	..	0.649	141	0.558	2006
183 बुर्किना फ़ासो	0.343	0.226	124	0.609	131	0.535	2010
184 चाड	0.340	0.203	130	..	..	0.344	2003

	मानव विकास सूचकांक (मा.वि.सू.)	असमानता समायोजित मा.वि.सू.		लैंगिक असमानता सूचकांक		बहु-आयामी निर्धनता सूचकांक	
मा.वि.सू. श्रेणी	मान	मान	श्रेणी	मान	श्रेणी	मान	श्रेणी
185 मोज़ाम्बीक	0.327	0.220	125	0.582	125	0.512	2009
186 कौंगो लोकतांत्रिक गणराज्य	0.304	0.183	132	0.681	144	0.392	2010
186 नाइजर	0.304	0.200	131	0.707	146	0.642	2006
अन्य देश अथवा क्षेत्र							
कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य	..	..	..	..	..	..	
मार्शल द्वीप समूह	..	..	..	..	..	..	
मोनाको	..	..	..	..	..	..	
नाउरू	..	..	..	..	..	..	
सैन मैरीनो	..	..	..	..	..	..	
सोमालिया	..	..	..	..	..	0.514	2006
दक्षिण सूडान	..	..	..	..	..	..	
तुवालू	..	..	..	..	..	..	
मानव विकास सूचकांक समूह							
अति उच्च मानव विकास	0.905	0.807	—	0.193	—	—	
उच्च मानव विकास	0.758	0.602	—	0.376	—	—	
मध्यम मानव विकास	0.640	0.485	—	0.457	—	—	
निम्न मानव विकास	0.466	0.310	—	0.578	—	—	
क्षेत्र							
अरब देश	0.652	0.486	—	0.555	—	—	
पूर्व एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र	0.683	0.537	—	0.333	—	—	
यूरोप एवं मध्य एशिया	0.771	0.672	—	0.280	—	—	
लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई क्षेत्र	0.741	0.550	—	0.419	—	—	
दक्षिण एशिया	0.558	0.395	—	0.568	—	—	
सब-सहारा अफ्रीका	0.475	0.309	—	0.577	—	—	
न्यूनतम विकसित देश	0.449	0.303	—	0.566	—	—	
छोटे द्वीपीय विकासशील देश	0.648	0.459	—	0.481	—	—	
विश्व	0.694	0.532	—	0.463	—	—	

नोट

सूचकांकों में अलग-अलग वर्षों के आँकड़े प्रयुक्त हुए हैं– विस्तृत जानकारी के लिए देखें सम्पूर्ण रिपोर्ट के सांख्यिकीय परिशिष्ट(यह उपलब्ध है http://hdr.undp.org पर), यहीं पर नोट्स और आँकड़ों के स्रोतों के बारे में भी सम्पूर्ण जानकारी मिलेगी। देशों के वर्गीकरण मा.वि.सू. क्वार्टाइल पर आधारित हैः सबसे ऊपर वाले क्वार्टाइल में स्थित मा.वि.सू. वाले देश को अति उच्च समूह में रखा गया है, अगर उसका मा.वि.सू. 51-75 पर्सेन्टाइल में है तो वह उच्च समूह में, यदि 26-50 पर्सेन्टाइल में है तो माध्य समूह में और निम्न समूह में यदि उसका मा.वि.सू. सबसे नीचे वाले क्वार्टाइल में है। पूर्ववर्ती रिपोर्टों ने निरपेक्ष के बजाय सापेक्ष थ्रेशोल्ड का प्रयोग किया था।

वैश्विक मानव विकास रिपोर्टें: विकास के मुद्दों, रुझानों और नीतियों की आनुभविक (empirical) पुष्टियों से परिपूर्ण और बौद्धिक रूप से स्वतंत्र विश्लेषणों के रूप में सन् 1990 से यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रकाशित होने वाली वैश्विक मानव विकास रिपोर्टों (मा.वि.रि.) की श्रृंखला की अद्यतन कड़ी है वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट। वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट से जुड़े अतिरिक्त संदर्भ-स्रोत hdr.undp.org पर निःशुल्क उपलब्ध हैं, इनमें 20 से भी अधिक भाषाओं में संपूर्ण रिपोर्ट या उसका सार-संक्षेप, वर्ष 2013 की इस रिपोर्ट के लिए प्रायोजित किए गए मानव विकास शोध पत्र, इंटरेक्टिव नक्शे तथा राष्ट्रीय मानव विकास संकेतक, रिपोर्ट के मानव विकास संकेतकों के लिए इस्तेमाल किए गए स्रोतों एवं कार्यविधियों की संपूर्ण व्याख्याएँ, देशों से जुड़े तथ्य और अन्य आधारिक जानकारियाँ शामिल हैं। पूर्व में प्रकाशित वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें (मा.वि.रि.) भी hdr.undp.org पर उपलब्ध हैं।

क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्टें: पिछले दो दशकों में यू.एन.डी.पी. के क्षेत्रीय ऑफ़िसों के सहयोग से विकासशील विश्व के सभी प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय फ़ोकस वाली मा.वि.रि. प्रकाशित हुई हैं। विचारोत्तेजत विश्लेषणों और दो टूक नीतिगत सुझावों वाली इन क्षेत्रीय मा.वि.रिपोर्टों ने अरब देशों में राजनीतिक सशक्तीकरण, अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा, एशिया में जलवायु परिवर्तन, मध्य यूरोप में जातीय अल्पसंख्यकों से होने वाले बर्ताव और लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियाई क्षेत्र में असमता व नागरिक सुरक्षा जैसे बेहद अहम मुद्दों की पड़ताल की है।

राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टें: सन् 1992 में पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद से यू.एन.डी.पी. के सहयोग और स्थानीय संपादकीय टीमों के प्रयासों से 140 देशों में राष्ट्रीय मा.वि.रि. प्रकाशित हो चुकी हैं। अब तक 700 से भी अधिक संख्या में प्रकाशित हो चुकी इन रिपोर्टों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परिसंवादों और शोध के द्वारा राष्ट्रीय नीति के सरोकारों में मानव विकास के दृष्टिकोण को पिरोने का काम हुआ है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्टों ने जलवायु परिवर्तन से लेकर युवाओं की बेरोज़गारी और जातीयता अथवा जेंडर आधारित असमानता सरीखे अहम विकास-मुद्दों को अपने विमर्श के दायरे में शामिल किया है।

मानव विकास रिपोर्टें 1990-2013

1990 मानव विकास की अवधारणा एवं मापन
1991 मानव विकास की वित्तीयन
1992 मानव विकास के वैश्विक आयाम
1993 जन भागीदारी
1994 मानव सुरक्षा के नए आयाम
1995 लैंगिकता एवं मानव विकास
1996 आर्थिक प्रगति एवं मानव विकास
1997 ग़रीबी उन्मूलन के लिए मानव विकास
1998 मानव विकास के लिए उपभोग
1999 मानवीयतापूर्ण वैश्वीकरण
2000 मानवाधिकार एवं मानव विकास
2001 नई प्रौद्योगिकियों को मानव विकास में सहायक बनाना
2002 विभाजित विश्व में लोकतंत्र को गहराना
2003 सहस्राब्दि विकास लक्ष्यः ग़रीबी मिटाने के लिए राष्ट्रों के बीच समझौता
2004 आज के वैविध्यपूर्ण विश्व में सांस्कृतिक आज़ादी
2005 अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दुविधाएँ: एक असमान विश्व में सहायता व्यापार एवं सुरक्षा
2006 अभावों के पारः ऊर्जा, ग़रीबी और वैश्विक जल संकट
2007/2008 जलवायु परिवर्तन से मुकाबलाः एक विभाजित विश्व में मानव-एकजुटता
2009 बाधाओं पर विजयः मानव गतिशीलता एवं विकास
2010 देशों की वास्तविक संपदाः मानव विकास के पथ
2011 संवहनीयता और समताः सबके लिए एक बेहतर भविष्य
2013 दक्षिण का उदयः विविधतापूर्ण विश्व में मानव विकास

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
एक, यूनाइटेड नेशन्स प्लाज़ा
न्यू यॉर्क, एन.वाई. 10017

www.undp.org

इस 21वीं सदी में वैश्विक गतिकी में एक बेहद गहरा बदलाव आता दीख रहा है, जो विकासशील दुनिया में तेज़ी से उभर रहे सत्ता केन्द्रों से परिचालित है। चीन ने जापान से आगे आकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल कर लिया है, इसके फलस्वरूप सैंकड़ों-लाखों लोगों को ग़रीबी के जाल से मुक्त करा लिया है। भारत एक नई उद्यमशील रचनात्मकता और सामाजिक नीति के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से अपने भविष्य को नए ढंग से गढ़ रहा है। ब्राज़ील अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विस्तार करके और ग़रीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के द्वारा जिस तरह अपना जीवन-स्तर उठाता जा रहा है, उसको आज दुनिया भर में अपनाया जा रहा है।

लेकिन 'दक्षिण का उदय' नाम की परिघटना इससे कहीं बड़ी है। इंडोनेशिया, मैक्सिको, दक्षिण अफ़्रीका, थाइलैंड, तुर्की और अन्य विकासशील देश विश्व मंच पर नायकों की भूमिका में नज़र आ रहे हैं। वर्ष 2013 की *मानव विकास रिपोर्ट* विकासशील दुनिया के 40 से भी अधिक ऐसे देशों को चिन्हित करती है, जिन्होंने हाल के दशकों में मानव विकास के संदर्भ में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है और पिछले कोई एक दशक से त्वरित प्रगति में उल्लेखनीय काम किया है।

इनमें से प्रत्येक देश का अपना एक अनूठा इतिहास है और हर एक ने अपने विकास का विशिष्ट रास्ता खुद चुना है। इसके बावजूद ये देश अनेक गुणधर्मों में एक से हैं और उनकी अनेक चुनौतियाँ भी समान हैं। उनकी आपसी निर्भरता बढ़ ही रही है, साथ ही पारस्परिक जुड़ाव के सूत्र भी मज़बूत हो रहे हैं। और समूचे विकासशील जगत के लोग अपनी आवाज़ सुने जाने को लेकर आग्रहीऔर मुखर हो रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास विचारों के आदान-प्रदान के लिए संवाद-संप्रेषण के नए माध्यम हैं और वे सरकारों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से अधिक जवाबदेही की माँग कर रहे हैं।

मानव विकास रिपोर्ट 2013 दक्षिण के उदय की इस लगातार जारी प्रक्रिया के कारणों और उसके परिणामों का विश्लेषण करती है और इस नई वास्तविकता के मूल में छिपी उन नीतियों की पहचान करती है जो आने वाले कई दशकों तक सारी दुनिया में और अधिक प्रगति की बयार बहाने में सहायक हो सकते हैं। यह रिपोर्ट वैश्विक अधिशासन व्यवस्थाओं में दक्षिण के बेहतर प्रतिनिधित्व का आह्वान करती है और अनिवार्य सार्वजनिक साधनों के लिए दक्षिण की ही परिधि के भीतर मौजूद संभावनायुक्त वित्तीयन स्रोतों की ओर इशारा करती है। ताज़ा और विश्लेषण-परक अंतर्दृष्टि से संपन्न और नीतिगत सुधारों के स्पष्ट प्रस्तावों से लैस यह रिपोर्ट प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों को मानव विकास की समान चुनौतियों का एकजुट होकर तथा पारदर्शी व प्रभावी तरीके से सामना करने का रास्ता तय करने में सहायता करती है।

''वैश्विक विकास की वर्तमान स्थिति की हमारी समझ को यह रिपोर्ट फिर ताज़ा करती है और दिखाती है कि दक्षिण के इतने सारे देशों की विकास की तेज़ प्रगति के अनुभवों से कितना कुछ सीखा जा सकता है।''

-यू.एन.डी.पी. प्रशासक हेलेन क्लार्क, आमुख में से

''मानव जीवन में आने वाली सफलताओं और वंचितताओं को ठीक से समझने, संवाद व चिंतन के मानव जीवन में महत्व की थाह पाने की दिक्कत से पार पाने के लिए मानव विकास का दृष्टिकोण एक अहम उपलब्धि है; साथ ही, यह दुनिया में पारदर्शिता और न्याय को बढ़ावा देने का ज़रिया भी है।''

-नोबल पुरस्कृत अमर्त्य सेन, पहले अध्याय से

''बेहतर विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है, और इसीलिए न्यूयार्क दूसरे शहरों और देशों में हो रहे अच्छे कामों से सीखने का सिलसिला जारी रखेगा।''

-न्यूयॉर्क शहर के मेयर माइकेल ब्लूमबर्ग, तीसरे अध्याय से

''सफल रहे विकासशील देशों द्वारा अपनाए गए अलग-अलग विकास पथों को क़रीब से देखने-समझने से सभी देशों और क्षेत्रों के नीतिगत विकल्पों की सूची समृद्ध होती है।''

-रिपोर्ट के प्रमुख लेखक ख़ालिद मलिक, प्रस्तावना से